

## My Notes.....

### राष्ट्रीय

#### बाहुबली ने अंतरिक्ष में पहुंचाया सबसे भारी सैटेलाइट

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) की सफलता गाथा में एक और अध्याय जुड़ गया है। 14 नवम्बर 2018 को इसरो ने बाहुबली कहे जाने वाले अपने सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी-एमके3-डी2 की मदद से देश के सबसे भारी और उन्नत संचार उपग्रह जीसैट-29 को कक्षा में स्थापित किया। यह उपग्रह पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट व अन्य संचार सुविधाएं मुहैया कराने में मददगार होगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस अभियान को इसलिए भी अहम माना है क्योंकि भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान-2 और मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों में इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जनवरी 2019 में भेजा जाने वाला चंद्रयान इस रॉकेट का पहला ऑपरेशनल अभियान होगा।

#### बाहुबली का बल

1. जीएसएलवी-एमके 3 इसरो द्वारा तैयार सबसे भारी रॉकेट है
2. 43.4 मीटर ऊंचे इस रॉकेट का वजन करीब 640 टन है
3. यह 4,000 किलो तक का पेलोड लेकर जाने में सक्षम है
4. इसी तरह के रॉकेट से पांच जून 2017 को जीसैट-19 सैटेलाइट भेजा गया था

#### जीसैट-29 सैटेलाइट पर एक नजर

1. 3,423 किलोग्राम वजन के साथ यह भारत का सबसे भारी सैटेलाइट है।
2. यह पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट व संचार सुविधाएं पहुंचाने में मददगार होगा
3. वैज्ञानिकों ने इसे केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के लिए अहम बताया है।
4. 10 साल के मिशन पर भेजे गए इस सैटेलाइट की सफलता से नई टेक्नोलॉजी का रास्ता खुलेगा।
5. इसके जरिये इसरो पहली बार लेजर आधारित ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम का परीक्षण कर रहा है

#### खाक से खास में बदले लद्दाख के घर को मिला यूनेस्को पुरस्कार

रखरखाव के अभाव में खाक में बदले पुरातन निर्माण शैली के एक भवन को शानदार मरम्मत कार्य के लिए यूनेस्को पुरस्कार मिला है। लद्दाख के इस भवन को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया-पैसिफिक पुरस्कार के तहत 'अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन' से सम्मानित किया गया है।

#### क्या है

1. औपनिवेशिक काल के मुंबई विश्वविद्यालय के राजाबाइ क्लॉक टॉवर और रत्नोन्सी मुलजी जेटा फाउण्डेन को संयुक्त रूप से चीन के एक प्रोजेक्ट के साथ 'ऑनरेबल मेशन' श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को ने एक बयान में इसकी घोषणा की है।
2. लद्दाख प्रोजेक्ट के पुरस्कार के लिए अपनी प्रशस्ति पत्र में जूरी ने कहा है कि इस भवन के दोबारा पुराने रूप में आने से कला संबंधी गतिविधियों के लिए सजीव स्थान मिला है, जो स्थानीय लोगों के साथ ही वहां आने वाले लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
3. लेह पैलेस में स्थित इस भवन का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था।



## पीएम ने शुरू की पहली कंटेनर कार्गो सेवा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में देश की पहली कंटेनर कार्गो सेवा की शुरुआत रामनगर बंदरगाह से की। यह बंदरगाह गंगा नदी पर हल्दिया-वाराणसी जलपरिवहन सेवा के तहत बनाया गया है। करीब 36 साल बाद देश की पहली जलपरिवहन परियोजना ने मूर्त रूप लिया। 1620 किलोमीटर लंबे वाराणसी-हल्दिया इनलैंड वाटर हाइवे का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इनलैंड वाटरवेज अथारिटी के अधिकारियों की माने तो इस परियोजना से पांच राज्यों की व्यावसायिक गतिविधियों में न केवल तेजी आएगी बल्कि एक साथ पांच सौ से दो हजार टन मॉल की ढुलाई का काम जलपरिवहन के जरिए हो सकेगा। वाहनों के चलते ध्वनि व वायु प्रदूषण में कमी आएगी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

क्या है

1. वर्ष 1982 में जल परिवहन मंत्रालय ने योजना पर काम शुरू किया था। मगर यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। वर्ष 2014 में नये सिरे से इस पर काम शुरू हुआ और चार साल के बाद देश में पहली बार कंटेनर कार्गो शुरू होने जा रही है।
2. इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक से करीब 5700 करोड़ रुपये की मदद ली है। योजना के पहले चरण में बनारस, साहेबगंज समेत पांच स्थानों पर बंदरगाह बनाने का काम चल रहा है।
3. इनलैंड वाटर अथारिटी के वाइस चेयरमैन प्रवीर पांडेय के मुताबिक पहले चरण की योजना का काम लगभग पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में 1500 से दो हजार टन के कंटेनर कार्गो का संचालन होगा।
4. हल्दिया-वाराणसी जलमार्ग परियोजना का ट्रायल वर्ष 2016 में हुआ। तब दो मालवाहक जहाज से कार और भवन निर्माण सामग्री की खेप आई थी। इसके बाद अब 12 नवंबर को रालहूपुर स्थित बंदरगाह पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का उत्पाद लेकर पहुंचा।
5. हल्दिया से एक हजार तीन सौ किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके पांच सौ टन माल लेकर शिपिंग कार्गो बनारस पहुंचा है। इस कार्गो पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का माल मंगाया गया है।
6. इसके पीछे मंशा इस नए जल परिवहन मार्ग को विश्व स्तर पर चर्चा में लाना है ताकि अधिक से अधिक मल्टीनेशनल कंपनियां इस व्यावसायिक परिवहन में दिलचस्पी दिखाएं, बजाय इसके कि उन्हें इसके लिए प्रेरित किया जाए। इस जलमार्ग से 20 टन माल, मात्र 15 हजार रुपये में 1318 किलोमीटर दूर तक पहुंचाया जा रहा है।

### रामनगर स्थित बंदरगाह एक नजर में

1. मल्टीमाडल टर्मिनल पर शुरू हुआ काम : वर्ष 2014
2. हल्दिया-वाराणसी परियोजना का ट्रायल : वर्ष 2016
3. पहली बार 16 कंटेनर के साथ पहुंचा कार्गो : 9 नवंबर, 2018
4. बंदरगाह के जेट्टी की लंबाई : 200 मीटर, चौड़ाई 42 मीटर
5. जेट्टी पर 02 मोबाइल हार्बर क्रेन
6. अप्रोच मार्ग, आंतरिक मार्ग

### खास बातें

1. बनारस-हल्दिया जलमार्ग से कई राज्यों की व्यावसायिक गतिविधियां तेज होंगी।
2. प्रदूषण कम होगा और माल सुरक्षित पहुंच सकेगा।
3. सड़क मार्ग के बजाए सस्ते दर पर एक साथ छह सौ टन माल की ढुलाई हो सकेगी।
4. रोड हाइवे का मेन जंक्शन होने और फ्रंट विलेज बनने से वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग-रैपिंग, कार्गो स्टोरेज, रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस सुविधा उपलब्ध होगी।
5. फिलहाल गंगा के जलस्तर को देखते हुए पांच सौ टन के मालवाहक जहाज चलेंगे
6. वाराणसी-पटना के बीच कम जलस्तर वाले स्थानों पर ड्रेजिंग का काम शुरू
7. भविष्य में दो हजार टन तक के जहाज चलाने की तैयारी

## भारत पुनः आईटीयू परिषद का सदस्य चुना गया

भारत अगले 4 वर्षों की अवधि (2019-2022) के लिए पुनः अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) परिषद का सदस्य चुना गया है। परिषद के चुनाव दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में चल रहे आईटीयू परिपूर्णता सम्मेलन 2018 के दौरान आयोजित किए गए। भारत 165 वोट प्राप्त करके एशिया-आस्ट्रेलिया क्षेत्र से परिषद के लिए चुने गए 13 देशों में तीसरे स्थान पर रहा और वैश्विक रूप से परिषद के लिए चुने गए 48 देशों में इसका स्थान 8वां रहा। आईटीयू के 193 सदस्य देश हैं जो परिषद में प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

### क्या है

1. भारत 1869 से आईटीयू का सक्रिय सदस्य रहा है, जो वैश्विक समुदाय देशों में संचार के विकास और प्रचार का गंभीरतापूर्वक समर्थन करता है।
2. भारत 1952 से आईटीयू परिषद का नियमित सदस्य रहा है और इस क्षेत्र के सदस्य देशों के योगदान को सुसंगत बनाने में इसने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने हमेशा समानता और सर्वसम्मति निर्माण के सिद्धांतों का आदर किया है।
3. विश्व को एक राष्ट्र और ज्ञान पूर्ण समाज के रूप में समझने के लिए भारत आईटीयू के स्वप्न और विजन को साझा करता है। आईटीयू के साथ मजबूत साझेदारी नई दिल्ली में आईटीयू दक्षिण एशिया क्षेत्र कार्यालय और प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र की स्थापना के अभी हाल में लिये गए आईटीयू के निर्णय से दिखाई देती है।

## ‘ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन’ शिखर सम्मेलन शुरू

आवासीय शीतलन (कूलिंग) प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा ‘ग्लोबल कूलिंग पुरस्कार’ की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय ‘ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन’ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में की गई। इसका उद्देश्य ऐसे आवासीय शीतलन (कूलिंग) प्रौद्योगिकी के विकास में तेजी लाना है, जिसका जलवायु पर असर मानक रूम एयर कंडीशनिंग (आरएसी) की तुलना में न्यूनतम पांचवां हिस्सा ही होगा।

### क्या है

1. इस पुरस्कार के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं इसके साझेदार संगठनों यथा विद्युत मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जरिए भारत सरकार के मिशन इनोवेशन द्वारा सहयोग दिया जा रहा है।
2. इसका संचालन प्रमुख अनुसंधान संस्थानों यथा रॉकी माउटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई), कंजर्वेशन X लैब्स, द एलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी (एईईई) और सीईपीटी विश्वविद्यालय के गठबंधन द्वारा किया जाएगा।
3. यह गठबंधन अभिनव प्रौद्योगिकी के इन्क्यूबेशन, वाणिज्यीकरण और अंततः व्यापक स्तर पर इसे अपनाने के प्रयासों को नई गति के साथ-साथ आवश्यक सहयोग भी देगा।
4. इसका शुभारंभ भारत से किया जाएगा और बाद में विश्व भर के अन्य देशों में इसका विस्तार किया जाएगा। इस प्रतिस्पर्धा में विजेता या चयनित साबित होने वाली प्रौद्योगिकी की बदौलत वर्ष 2050 तक 100 गीगाटन (जीटी) के समतुल्य कार्बन डाई आक्साइड (सीओ<sub>2</sub>) के उत्सर्जन की रोकथाम हो सकेगी और इसके साथ ही दुनिया वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की कमी करने के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगी।
5. दो वर्ष तक चलने वाली इस प्रतिस्पर्धा के दौरान पुरस्कार राशि के रूप में 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक की रकम प्रदान की जाएगी। मध्यवर्ती पुरस्कारों के तहत 10 चयनित प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियों में से प्रत्येक के लिए पुरस्कार के रूप में दो लाख अमेरिकी डॉलर तक की राशि दी जाएगी।
6. इसका उद्देश्य संबंधित अभिनव आवासीय शीतलन प्रौद्योगिकी के डिजाइन के साथ-साथ इसके प्रारूप (प्रोटोटाइप) के विकास के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना है।

7. इस प्रतिस्पर्धा में विजेता साबित होने वाली प्रौद्योगिकी के लिए पुरस्कार के रूप में कम से कम एक मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाएगी, ताकि इसके इन्क्यूबेशन और आरंभिक चरण में इसके वाणिज्यीकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके।
8. वर्तमान में विश्व भर में 1.2 अरब रूम एयर कंडीशनिंग यूनिटें कार्यरत हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक रूम एयर कंडीशनिंग यूनिटों की संख्या बढ़कर कम से कम 4.5 अरब के आंकड़े को छूने लगेगी।
9. अकेले भारत में वर्ष 2050 तक बाजार में एक अरब से भी अधिक रूम एयर कंडीशनिंग यूनिटों को पेश कर दिया जाएगा। आरामदेह कूलिंग प्रदान करने में होने वाली ऊर्जा खपत की भी गिनती जलवायु के लिए सर्वाधिक जोखिमपूर्ण माने जाने वाले कारकों (फेक्टर) में की जाती है और इस वजह से सर्वाधिक कमजोर एवं असुरक्षित मानी जाने वाली आबादी का स्वास्थ्य खतरे में पड़ता नजर आ रहा है।

### हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल गठित

पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के सतत विकास के लिए नीति आयोग ने 'हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल' का गठन किया है। नीति आयोग के सदस्य डा. वी के सारस्वत की अध्यक्षता वाली इस काउंसिल में हिमालयी राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव बतौर सदस्य शामिल होंगे।

क्या है

1. जिन हिमालयी राज्यों के विकास पर यह काउंसिल फोकस करेगी उसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं।
2. साथ ही इसमें असम और पश्चिम बंगाल के दो-दो जिले भी शामिल हैं।
3. यह काउंसिल हिमालयी राज्यों में चल रहे विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। साथ ही हिमालयी राज्यों में जल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी बेसिन विकास पर भी फोकस करेगी।
4. इसके अलावा इन राज्यों में पर्यटन विकास के लिए मानकों के निर्धारण तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी भी जोर देगी।

### ऑपरेशन ग्रीन के लिए मार्ग-निर्देश जारी

केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 5 नवम्बर 2018 ऑपरेशन ग्रीन के लिए संचालन संबंधी उपायों को अपनी मंजूरी दे दी है। देशभर में पूरे वर्ष तक मूल्यों में उतार-चढ़ाव के बिना टमाटर, प्याज और आलू की आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 2018-19 के बजट भाषण में 500 करोड़ रुपये की लागत से ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की थी। इस क्रांतिकारी योजना से सभी हितधारकों के साथ निरंतर वार्ता के बाद तैयार किया गया। देशभर में पूरे वर्ष तक सभी परिवारों तक इन फसलों की पहुंच सुनिश्चित करना इन उपायों का उद्देश्य है।

मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:-

1. लघुकालिक मूल्य स्थिरीकरण उपाय  
मूल्य स्थिरीकरण उपाय को लागू करने में नेफेड शीर्ष एजेंसी होगा। निम्नलिखित दो घटकों पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 50 प्रतिशत सब्सिडी देगा।
  1. उत्पादन से लेकर भंडार तक आलू, प्याज और टमाटर फसलों की ढुलाई;
  2. टमाटर, प्याज और आलू फसलों के लिए समुचित भंडार सुविधाओं का किराया;
2. दीर्घकालिक समन्वित मूल्य शृंखला विकास परियोजना
  1. किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और उनके केंद्रों का क्षमता निर्माण
  2. गुणवत्तापूर्ण उत्पादन
  3. फसल पश्चात् प्रसंस्करण सुविधा

4. कृषि उपस्कर
5. विपणन / उपभोग केंद्र
6. टमाटर, प्याज और आलू फसलों की मांग और आपूर्ति प्रबंधन के लिए ई-प्लेटफॉर्म का निर्माण और प्रबंधन

#### अन्य महत्वपूर्ण उपाय

1. सभी क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता इस प्रणाली में शामिल होगी, बशर्ते प्रति परियोजना अधिकतम 50 करोड़ रुपये हो।
2. हालांकि, जिस मामले में पीआईई ही एफपीओ हो, सभी क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 70 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, बशर्ते प्रति परियोजना अधिकतम 50 करोड़ रुपये हो।
3. पात्र संगठन में राज्य कृषि और अन्य विपणन परिसंघ, किसान उत्पादक संगठन, सहकारी संगठन, कंपनी, स्व-सहायता समूह, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, उपस्कर ऑपरेटर, सेवाप्रदाता, आपूर्ति शृंखला ऑपरेटर, खुदरा और थोक शृंखला तथा केंद्रीय और राज्य सरकार तथा उनकी इकाइयां/संगठन शामिल हैं, जो इस कार्यक्रम में भाग लेने के साथ ही वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

#### चयनित क्लस्टरों की सूची

##### क. टमाटर का उत्पादन क्लस्टर:

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन क्लस्टर क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर और अनंतपुर(खरीफ और रबी फसल)
2.	कर्नाटक	कोलार और चिक्करबल्लापुर(खरीफ फसल)
3.	ओडिशा	मयूरभंज और क्योबझर(रबी फसल)
4	गुजरात	साबरकांठा

##### ख. प्याज का उत्पादन क्लस्टर:

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन क्लस्टर क्षेत्र
1.	महाराष्ट्र	नासिक (रबी फसल)
2.	कर्नाटक	गडग और धारवाड़ (खरीफ फसल)
3.	गुजरात	भावनगर और अमरेली
4.	बिहार	नालंदा

##### ग. आलू उत्पादन क्लस्टर:

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन क्लस्टर क्षेत्र
1.	उत्तर प्रदेश	(क)आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस और अलीगढ़ (ख) फर्रुखाबाद और कन्नौज
2.	पश्चिम बंगाल	हुगली और पूर्वा बर्धमान
3.	बिहार	नालंदा
4.	गुजरात	बनासकांठा और साबरकांठा

## भारत से पहली पैसेंजर ट्रेन पहुंची नेपाल

भारत से पहली बार पैसेंजर ट्रेन पहुंचने पर नेपाल में हर्ष का माहौल है। 4 नवम्बर 2018 को ट्रायल के तहत ट्रेन बिहार के बथनाहा से नेपाल के मोरंग पहुंची, तो हजारों लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। ट्रेन के दोनों तरफ भारत और नेपाल के झंडे लगे थे। यह रूट 18.1 किलोमीटर का है, जिसका 13.1 किलोमीटर हिस्सा नेपाल में पड़ता है। इस परियोजना का अनुमानित खर्च 4,800 करोड़ रुपया है। यह राशि आर्थिक सहयोग के तहत भारत ने नेपाल को उपलब्ध कराई है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ब्रॉड गेज पर पहले यात्री ट्रेन के इस साल दिसंबर में शुरू होने की संभावना है। नई दिल्ली में रेलवे के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

क्या है

1. यह ट्रेन बिहार में जयनगर से नेपाल में जनकपुर जोन के धनुषा जिले के कुर्था तक चलेगी। जयनगर--कुर्था रेलखंड की लंबाई 34 किलोमीटर है।
2. सूत्रों ने बताया कि जयनगर में संभवतः एक आव्रजन चेक नाका बनाया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी आव्रजन ब्यूरो या राज्य सरकार की होगी। इस रास्ते से आने-जाने के लिए भारतीय और नेपाली नागरिकों को वीसा की जरूरत नहीं होगी।
3. नेपाली अधिकारियों ने रेलवे को सूचित किया है कि यह सेक्शन चार यात्राओं के लिए खुला रहेगा और आठ से 16 घंटे की शिफ्ट में काम करेगा। इस रूट पर पहली ट्रेन यात्री गाड़ी होगी, लेकिन नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि वे यात्री और माल गाड़ी दोनों चलाना चाहते हैं।
4. नेपाल इस रूट के लिए भारत से रैक, कोच और अन्य चीजें लीज पर ले रहा है। इसे नेपाल के साथ रेल यातायात संपर्क जोड़ने के चीन के प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है।
5. नेपाल और भारत के बीच चार अलग अलग स्थानों पर रेलवे लाइन बिछाने की योजना है, इनमें से एक रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने वाला है।

## आयुर्वेद दिवस मनाया गया

आयुष मंत्रालय प्रत्येक वर्ष धनवंतरी जयंती के अवसर पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार आयुर्वेद दिवस 5 नवंबर को मनाया गया। इस उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय नीति आयोग के साथ मिलकर 4 और 5 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में आयुर्वेद में उद्यमिता और व्यापार विकास पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और उद्यमियों को कारोबार के नए अवसरों के प्रति जागरूक करना है।

क्या है

1. यह संगोष्ठी आयुर्वेद उत्पादों की बाजार हिस्सेदारी 2022 तक तीन गुना करने के आयुष मंत्रालय द्वारा तय किए गए बड़े लक्ष्य की दिशा में उठाया गया एक कदम है।
2. संभावना है कि संगोष्ठी के माध्यम से व्यापार के अवसरों के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा की जा सकेगी, युवा उद्यमियों को नई प्रौद्योगिकी और नवाचारों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा तथा वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद उत्पादों के लिए अवसरों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
3. संगोष्ठी में विपणन, वित्तीय प्रबंधन, नवाचार, टेली मेडिसिन और स्टार्टअप के विशेषज्ञ तथा नीति निर्माता और आयुर्वेद फार्मा और चिकित्सा उद्योग क्षेत्र के अनुभवी लोग प्रतिभागियों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे और उनका मार्ग दर्शन करेंगे।
4. संगोष्ठी के दौरान होने वाली चर्चाओं के माध्यम से युवा उद्यमियों को आयुर्वेद क्षेत्र में कारोबार की विभिन्न संभावनाओं, नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के तरीके तथा कारोबार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं की जानकारी मिलने की संभावना है।
5. आयुष मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस कथन को साकार करना चाहता है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे युवा उद्यमियों के लिए समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं और



- आईटी क्षेत्र में पिछले 30 सालों में जो क्रांति आई है उसके अब आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी आने का समय आ गया है।
6. तीसरे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में देशभर से करीब 800 प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। आयुर्वेद क्षेत्र के जानेमाने वैद्यों को इस दिन 'राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार' से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, धनवंतरी की प्रतिमा वाली ट्राफी और पांच लाख रुपये नकद दिए जाएंगे।
  7. इस बार यह पुरस्कार आयुर्वेद के जानेमाने विशेषज्ञ वैद्य शिव कुमार मिश्रा, वैद्य माधव सिंह भगेल और इतुजी भवदासन नंबूदरी को दिया जाएगा। इनका चयन आयुष मंत्रालय ने किया है।
  8. नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई आयुर्वेद प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं को भी समारोह में सम्मानित किया जाएगा।
  9. तीसरे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 5 नवंबर को आयुष स्वास्थ्य प्रणाली का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड रखने के लिए आयुष-स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (ए-एचएमआईएस) के नाम से एक समर्पित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन लांच किया जाएगा।
  10. इसे शुरूआती चरण में देश के विभिन्न हिस्सों में 15 आयुष इकाइयों में शुरू किया जाएगा। इससे आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा के तरीकों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

## 6 एयरपोर्ट को लीज पर देने के लिए मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छह हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) योजना के तहत लीज पर दिए जाने के लिए मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु हवाई अड्डों के लिए ये अहम फैसला सुनाया। पीपीपीएसी के कार्यक्षेत्र से बाहर के किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तथा व्यय विभाग के सचिव को शामिल करके सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया जायेगा। क्या है

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व वाले इन हवाई अड्डों का प्रबंधन पीपीपी के तहत किया जाएगा। पीपीपीएसी के अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी मुद्दे को निपटाने के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह को जिम्मेदारी दी जाएगी।
2. पीपीपी मॉडल के तहत प्रबंध किए जा रहे हवाई अड्डों में दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि शामिल हैं।
3. हैदराबाद और बंगलुरु में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए पीपीपी मॉडल से बुनियादी ढांचा परियोजना में हवाई अड्डों पर विश्व श्रेणी का बुनियादी ढांचा जुटाने, हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों को कुशल और समयबद्ध सेवाओं की आपूर्ति करने और बिना किसी निवेश के भारतीय विमान प्राधिकरण की राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने में मदद मिली है।
4. भारत में पीपीपी हवाई अड्डों ने हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता (एसक्यू) के रूप में हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय परिषद (एसीआई) द्वारा अपनी संबंधित श्रेणियों में शीर्ष पांच हवाई अड्डों में रैंक हासिल की है।

## सिमबेक्स 2018 की 25वीं वर्षगांठ

भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास-सिमबेक्स 10 से 21 नवंबर 2018 के बीच अंडमान समुद्र और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। यह सिमबेक्स की 25वीं वर्षगांठ होगी। भारत और सिंगापुर के बीच नौसैनिक सहयोग की शुरूआत 1994 में हुई थी, जब सिंगापुर नौसेना के जहाजों ने भारतीय नौसेना के

साथ प्रशिक्षण आरंभ किया था। मुख्यतः एंटी सबमरीन वॉर फेयर के रूप में शुरू हुआ यह सहयोग अब और ज्यादा व्यापक हो चुका है। हाल के वर्षों में इसमें विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आधुनिक अभ्यास भी शामिल हो चुके हैं।

**क्या है**

1. भारत की 'ऐक्ट ईस्ट नीति' पर अमल करते हुए हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय वार्ताएं और समझौते किए गए हैं, जिससे परस्पर संबंध और प्रगाढ़ हो रहे हैं।
2. भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ ही संयुक्त अभ्यासों और अन्य द्विपक्षीय सहयोग के लिए 20 से ज्यादा व्यवस्थाएं की गई हैं, जिन पर हर साल अमल किया जाता है।

3. नवंबर 2015 में दोनों देशों के बीच इन संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया गया।

4. इस वर्ष जून में शंगरिला डॉयलॉग से इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लूंग ने रक्षा और रणनीतिक साझेदारी के अलावा कई और क्षेत्रों में भी परस्पर सहयोग के कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

5. इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच किया गया

कार्यान्वयन समझौता था, जो आपसी समन्वयन, नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों और नौसेना के विमानों के रखरखाव और लाजिस्टिक्स से संबंधित है।

6. इस समझौते के लागू होने के साथ ही दोनों देश अपने नौसैनिक संसाधनों को लाजिस्टिक्स और सेवाओं के जरिए एक-दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं।
7. समझौते के माध्यम से भारत और सिंगापुर अपने साझा समुद्री क्षेत्र में अपने सहयोगी देशों के साथ नियमित रूप से संयुक्त अभ्यास करने पर सहमत हुए हैं। करार पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत और सिंगापुर की नौसेना द्वारा संयुक्त अभ्यास और पेशेवर साझेदारी बनाए रखने की सराहना की और **संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की 25वीं वर्षगांठ मनाए जाने की उम्मीद जताई।** इससे पहले दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दक्षिणी चीन सागर में मई 2017 में आयोजित किया गया था।

8. इस साल अपनी 25वीं वर्षगांठ को ऐतिहासिक बनाने के लिए दोनों देशों की नौसेनाओं ने अभ्यास क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं को विस्तार दिया है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व रणवीर श्रेणी का विध्वंसक

#### फ्लैशपॉइंट

1. भारत और सिंगापुर के बीच 1994 से शुरू हुए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का इस बार का संस्करण सबसे बड़ा होगा। शुरूआती चरण में बंदरगाह स्तर पर इसका आयोजन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की राजधानी पोर्टब्लेयर में 10 से 12 नवंबर के बीच किया जाएगा।
2. इसके बाद समुद्री क्षेत्र में अभ्यास की शुरूआत 12 से 16 नवंबर तक अंडमान सागर में होगी। बंदरगाह स्तर पर अभ्यास का दूसरा चरण विशाखापट्टनम में 16 से 19 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा।
3. इस अवसर पर सिमबेक्स की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन होगा, पेशेवर और प्रशिक्षण स्तर पर अनुभवों का आदान-प्रदान किया जाएगा, 10 किलोमीटर लंबी मित्रता दौड़ ख विशाखा नेवी मैराथन दौड़ आयोजित की जाएगी और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।
4. समुद्री क्षेत्र में अभ्यास का अंतिम चरण 19 से 21 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
5. सिमबेक्स के 25वें संस्करण के दौरान समुद्र में विध्वंसक पोत मिसाइल दागने के अलावा अपने अन्य हथियारों का जीवंत प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान बड़े तारपीडो तथा मध्यम दूरी तक मार करने वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट एडवांस पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली का भी प्रदर्शन किया जाएगा। अभ्यास के दौरान समुद्री गश्ती हेलीकॉप्टर और विमान भी अपनी क्षमता और कौशल का प्रदर्शन करेंगे।



- पोत रणविजय, आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस सहयाद्रि, आईएनएस कदमत, आईएनएस कीर्च, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस सुकन्या कर रहे हैं।
9. इन विध्वंसक पोतों के काफिले के साथ ही सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस शक्ति और आईएनएस सिंधु कीर्ति भी शामिल रहेंगी। नौसैनिक अभ्यास में समुद्री गश्ती विमान डॉर्नियर 228, पी81, एमके132 हॉक और यूएच3एच तथा चेतक हेलीकॉप्टर भी रहेंगे।
  10. नौसैनिक अभ्यास में सिंगापुर की नौसेना की ओर से दो स्टील्थ विध्वंसक पोत आरएसएस फॉर्मिडेबल और आरएसएस स्टीडफास्ट, एक लिटोरल मिशन पोत - आरएसएस यूनिटी, मिसाइल युक्त दो पोत- आरएसएस विगर और आरएसएस वैलिगंट, एक आर्चर श्रेणी की पनडुब्बी आरएसए स्वडर्समैन, गहरे समुद्र में त्वरित बचाव करने वाला जहाज डीएसआरवी, एक समुद्री गश्ती जहाज फोकर एफ50, एस70बी हेलीकॉप्टर तथा मानवरहित विमान स्कैन ईगल भाग लेंगे।
  11. भारत की ओर से इस बार के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व पूर्वी नौसैनिक कमान के रीयर एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी करेंगे। जबकि सिंगापुर की नौसेना का नेतृत्व डिप्टी कमांडर टास्क ग्रुप हो जी केन और कर्नल लिम यू चुआन करेंगे।

## युवा उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए स्टार्टअप योजना की शुरुआत

युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की सरकार की योजना को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय कृषि व सहकारिता मंत्री राधा मोहन सिंह ने युवा सहकार उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की 1000 करोड़ रुपये की 'युवा सहकार उद्यम सहयोग व नवाचार योजना' को लांच करने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप योजना को रफ्तार देने और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है।

### क्या है

1. योजना को आकर्षक बनाने के लिए इसमें दिए जाने वाले कर्ज की सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के लाभार्थियों के लिए कुछ प्रावधानों को सरल बना दिया गया है। इसके तहत ब्याज में दो फीसद की रियायत दी जाएगी।
2. कर्ज लौटाने की अवधि दो साल बाद शुरू की जाएगी। इससे उद्यमियों को अपना उद्योग जमाने में पूरी मदद मिलेगी। सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि देश में कुल आठ लाख सहकारी संस्थाएं हैं।
3. ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाने और युवाओं को इसमें लाने के लिए इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। तीन साल पुरानी रजिस्ट्रेशन वाली संस्थाओं की जगह एक साल पहले रजिस्टर्ड हुई सहकारी संस्थाओं को भी इसका लाभ दिया जाएगा।
4. सिंह ने बताया कि एनसीडीसी ने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के वर्ष 2010-14 के कार्यकाल में 19,850 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किए थे, जबकि वर्तमान राजग सरकार के वर्ष 2014-18 के कार्यकाल में कुल 63,702 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किए गए।

## अन्तरराष्ट्रीय

### आरसीईपी की सातवीं अंतर-सत्र मंत्रिस्तरीय बैठक संपन्न

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 12-13 नवंबर, 2018 को सिंगापुर में आयोजित आरसीईपी (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी) की सातवीं अंतर-सत्र मंत्रिस्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सिंगापुर के व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री चान चुन सिंग ने इस बैठक की अध्यक्षता की क्योंकि सिंगापुर ही इस वर्ष आसियान की अध्यक्षता संभाल रहा है। सिंगापुर में 14 नवंबर, 2018 को आयोजित होने वाली द्वितीय आरसीईपी लीडर्स समिट की तैयारी के सिलसिले में यह मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी शिरकत करेंगे।

### क्या है

1. **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी ( आरसीईपी )** एक मेगा या व्यापक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता है जिसके लिए 16 देशों के बीच वार्ताएं जारी हैं।
2. इन 16 देशों में आसियान के 10 देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम) और **आसियान एफटीए ( मुक्त व्यापार समझौता )** के छह साझेदार देश यथा आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। अब तक छह मंत्रिस्तरीय बैठकें, सात अंतर-सत्रात्मक मंत्रिस्तरीय बैठकें और तकनीकी स्तर पर व्यापार वार्ता समिति के 24 दौर आयोजित किए जा चुके हैं।
3. इस दौरान मंत्रियों ने विभिन्न अध्यायों से जुड़ी वार्ताओं की ताजा स्थिति का जायजा लिया। व्यापार वार्ता समिति के अध्यक्ष श्री पाक ईमान पैमबैग्यो ने आरसीईपी से जुड़ी वार्ताओं की ताजा स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी और लंबित मुद्दों पर मंत्रिस्तरीय मार्गदर्शन किए जाने की गुजारिश की।
4. आरसीईपी से जुड़ी बैठक के दौरान वाणिज्य मंत्री ने सिंगापुर, चीन, जापान और न्यूजीलैंड के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय मुद्दों के साथ-साथ आरसीईपी से जुड़ी वार्ताओं में हुई प्रगति के बारे में विचार-विमर्श किया। उन्होंने आपसी हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, आस्ट्रेलिया और फिलीपींस के व्यापार मंत्रियों के साथ भी बैठकें कीं।
5. **मंत्रियों ने यह माना कि संबंधित वार्ताओं में अब तक अच्छी प्रगति हुई है।** इन वार्ताओं के तहत अकेले इसी वर्ष पांच अध्यायों का सफल समापन हो चुका है।

### अब तक कुल मिलाकर इन सात अध्यायों का सफल समापन हुआ है

1. आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग
2. छोटे एवं मझोले उद्यम
3. सीमा शुल्क से जुड़ी प्रक्रियाएं एवं व्याहार को सुविधाजनक बनाना
4. सरकारी खरीद
5. संस्थागत प्रावधान
6. मानक, तकनीकी नियमन एवं अनुरूप आकलन प्रक्रियाएं (एसटीआरएसीएपी)
7. स्वकच्छता (सैनिटरी) एवं पादप स्वच्छता (फाइटोसैनिटरी) यानी एसपीएस।

### ईरान से तेल खरीद सकता है भारत

अमेरिका भारत के अलावा सात अन्य देशों को ईरान से तेल खरीदने की छूट देने पर राजी हो गया है। छूट प्राप्त करनेवाले देशों में जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल होंगे। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि ईरान से तेल आयात पर नए सिरों से लग रही अमेरिकी पाबंदी 5 नवंबर से प्रभावी हो जाएगी। खबर है कि अमेरिका न्यूक्लियर डील पर ईरान से नए सिरों से बातचीत करना चाहता है, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है।

### क्या है

1. ईरान को बातचीत के लिए मजबूर करने के इरादे से ही अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करना चाहता है और इसलिए उसने दुनिया के कई देशों को 4 नवंबर के बाद से ईरान से तेल आयात पर रोक लगाने की बात कही है।
2. अमेरिका कुछ देशों को जरूरी शर्त के साथ तेल आयात में छूट दे रहा है लेकिन, बताया जा रहा है कि जो देश ईरान से तेल आयात करेंगे वे धीरे-धीरे तेल खरीद की मात्रा घटाते रहेंगे।
3. ईरानी तेल का सबसे बड़ा आयातक चीन छूट पाने की शर्तों को लेकर अब भी अमेरिका से बातचीत कर रहा है। लेकिन भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के अलावा छूट प्राप्त करनेवाले चार देश कौन से हैं, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है।

4. तेल बाजार को इस बारे में खबर मिलने के बाद कि अमेरिका कुछ देशों को तेल आयात में छूट दे रहा है पिछले महीने ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का भाव 15 फीसद गिरकर 85 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि जिन देशों को ईरान से तेल खरदीने में छूट मिली है वह कितनी मात्रा में तेल का आयात कर सकते हैं।

### भारत और रूसी संघ के बीच समझौता ज्ञापन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को रूस के साथ 05 अक्टूबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) तथा एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) की जानकारी दी गई।

1. परिवहन शिक्षा में सहयोग विकास के लिए रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन।
2. रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर संयुक्त स्टॉक कंपनी 'रूसी रेलवे' (आरजेडडी) के साथ सहयोग ज्ञापन।  
एमओयू / एमओसी भारतीय रेल को रेल क्षेत्र में नवीनतम विकास और ज्ञान साझा करने का मंच प्रदान करते हैं। एमओयू / एमओसी विशेष प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर फोकस करने वाले तकनीकी विशेषज्ञों, रिपोर्टों तथा तकनीकी दस्तावेजों, प्रशिक्षण और संगोष्ठियों / कार्यशालाओं का आदान-प्रदान करने तथा ज्ञान साझा करने में सहायता देते हैं। एमओयू में परिवहन शिक्षा के विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान है। समझौता ज्ञापन व्यापार-आर्थिक, वैज्ञानिक-तकनीकी तथा सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर-सरकारी रूसी - भारतीय आयोग के ढांचे में क्रियान्वयन सहित विशेष प्रस्तावों की तैयारी में सहायता देगा।

एमओसी निम्नलिखित क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग में सहायता देगा

1. यात्री गाड़ियों की गति 200 किलोमीटर प्रतिघंटे (सेमी हाई स्पीड) बढ़ाने के लिए नागपुर-सिकंदराबाद सेक्शन के उन्नयन के लिए परियोजना को लागू करना। इसमें भारतीय रेल नेटवर्क के अन्य निर्देशों सहित सेक्शन का संभावित विस्तार शामिल है।
2. क्षेत्रीय स्तर, मंडलीय रेल या जोनल रेलवे को जोड़ने वाले ऊपरी नेटवर्क स्तर पर मिले-जुले यातायात के प्रबंधन के लिए एकल ट्रेफिक नियंत्रण केन्द्र लागू करना।
3. विशिष्ट निर्माण, संयुक्त निर्माण का संगठन तथा स्पर्धी सिग्नलिंग और इंटर-लॉकिंग प्रणाली को लागू करना।
4. सेमी हाई स्पीड तथा इससे ऊपर के लिए टर्नआउट स्विचों की आपूर्ति और एकत्रीकरण।
5. रूसी रेल से जुड़े उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानों की भागीदारी के साथ भारतीय रेल के कर्मचारियों की प्रशिक्षण तथा एडवांस योग्यता सुधार।
6. माल ढुलाई कार्गो संचालन में श्रेष्ठ व्यवहार तथा
7. भारत में मल्टी मॉडल टर्मिनलों का संयुक्त विकास।

#### पृष्ठभूमि

1. भारतीय रेल ने विभिन्न विदेशी सरकारों तथा राष्ट्रीय रेलवे के साथ रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए एमओयू / एमओसी पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. सहयोग के चिन्हित क्षेत्रों में उच्च गति की रेलगाड़ी, वर्तमान मार्गों की गति बढ़ाना, विश्व स्तरीय स्टेशनों का विकास, भारी परिवहन संचालन रेल ढांचे का आधुनिकीकरण शामिल है।
3. यह सहयोग रेलवे टेक्नोलॉजी तथा संचालन ज्ञान का आदान-प्रदान, तकनीकी यात्राओं, प्रशिक्षण तथा संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के माध्यम से परस्पर हित के क्षेत्रों में किया जाता है।

### भारत और कोरिया के मध्य समझौता ज्ञापन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और कोरिया के मध्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है।

इस समझौता ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं

1. पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करना।
2. पर्यटन से संबंधित जानकारी और डाटा के आदान-प्रदान को बढ़ाना।
3. होटलों और टूर ऑपरेटर्स सहित पर्यटन हितधारकों के मध्य- सहयोग को प्रोत्साहन देना।
4. मानव संसाधन विकास में सहयोग के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रमों को स्थापित करना।
5. पर्यटन और आतिथ्य सत्कार क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना।
6. दोतरफा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए टूर ऑपरेटर्स/मीडिया/जनमत निर्माताओं की यात्राओं का आदान-प्रदान।
7. संवर्धन, विपणन गंतव्य विकास और प्रबंधन के क्षेत्रों में अनुभव का आदान-प्रदान करना।
8. एक-दूसरे के देश में यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
9. सुरक्षित, सम्मानित और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना।

#### पृष्ठभूमि

1. भारत और कोरिया के मध्य मजबूत राजनयिक और दीर्घकालीन आर्थिक संबंध मौजूद हैं।
2. दोनों पक्ष अब पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मौजूदा संबंधों को ज्यादा मजबूत तथा विकसित करना चाहते हैं।
3. कोरिया, पूर्व एशिया से भारत के लिए शीर्ष पर्यटक जुटाने वाले बाजारों में से एक देश है।
4. कोरिया के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से इस संसाधन बाजार से भारत में पर्यटकों का आगमन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

#### बच्चों के लिए नरक है यमन: संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने 4 नवम्बर 2018 को कहा कि युद्धग्रस्त यमन बच्चों के लिए 'जीता-जागता नरक' बन चुका है, जहां हजारों बच्चे कुपोषण और उन बीमारियों से हर साल मर रहे हैं, जिनका आसानी से इलाज किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी यूनिसेफ में दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रीय निदेशक गीर्ट कैप्लेयर ने संबंधित पक्षों से इस महीने के आखिर में होने वाली शांति वार्ता में शामिल होने और संघर्षविराम पर राजी होने का आह्वान किया। उन्होंने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया, 'यमन आज के समय में जीता-जागता नरक बन चुका है-- न केवल 50 से 60 फीसदी बच्चों के लिए, बल्कि यमन हर लड़के और लड़की के लिए एक नरक है।

क्या है

1. यह आंकड़े हम सभी को यह समझने के लिए एक चेतावनी है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है।
2. यूनिसेफ के मुताबिक, यमन में पांच साल से नीचे की उम्र के करीब 18 लाख बच्चे भयंकर रूप से कुपोषण से ग्रस्त हैं, उनमें से गंभीर रूप से प्रभावित चार लाख बच्चों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है।
3. यमन में हर एक साल 30,000 बच्चों की जान कुपोषण की वजह से चली जाती है जबकि हर एक 10 मिनट में एक बच्चे की मौत उन बीमारियों से हो जाती है, जिनका इलाज आसानी से किया जा सकता है।

#### चीन में उड़गरों पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता

संयुक्त राष्ट्र में 6 नवम्बर 2018 को एक समीक्षा के दौरान चीन को मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। इस दौरान विभिन्न देशों ने उड़गरों की सामूहिक हिरासत और नागरिक स्वतंत्रताओं के खिलाफ कार्रवाई पर चिंता जताई। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में आधे दिन की सार्वजनिक चर्चा के दौरान कई देशों ने उड़गर मुस्लिमों और तिब्बतियों सहित जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ चीन के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की गई।

### क्या है

1. चर्चा के दौरान करीब 500 लोगों ने संयुक्त राष्ट्र के बाहर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने बैनर ले रखे थे जिन पर लिखा था, 'चीन, उइगरों का नरसंहार रोको' और 'तिब्बत मर रहा है, चीन झूठ बोल रहा है।'
2. 'यूनीवर्सल पिरियोडिक रीव्यू' में सभी 193 देशों को लगभग हर चार साल पर जाना होता है। संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र समिति द्वारा हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार, चीन में करीब 10 लाख उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को क्षेत्र में न्यायोत्तर हिरासत में रखा गया है।
3. इसे चर्चा के दौरान दोहराया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चीन के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को बड़ी दाढ़ी रखने और हिजाब पहनने के लिए बिना वजह ही हिरासत में ले लिया जाता है।

### अमेरिका ने कुछ प्रतिबंधों से भारत को छूट दी

अमेरिका ने ईरान में विकसित किए जा रहे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह और इसे अफगानिस्तान से जोड़ने वाली रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भारत को कुछ प्रतिबंधों से छूट दे दी है। ट्रंप प्रशासन का यह फैसला दिखाता है कि ओमान की खाड़ी में विकसित किए जा रहे इस बंदरगाह में भारत की भूमिका को अमेरिका मान्यता देता है।

### क्या है

1. इसे इस तरह समझा जा सकता है कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए और छूट देने में उसका रुख बेहद सख्त है।
2. यह बंदरगाह युद्ध ग्रस्त अफगानिस्तान के विकास के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3. विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि गहन विचार के बाद विदेश मंत्री ने 2012 के ईरान स्वतंत्रता एवं प्रसार रोधी अधिनियम के तहत लगाए गए कुछ प्रतिबंधों से छूट देने का प्रावधान किया है जो चाबहार बंदरगाह के विकास, उससे जुड़े एक रेलवे लाइन के निर्माण और बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान के इस्तेमाल वाली, प्रतिबंध से अलग रखी गई वस्तुओं के नौवहन से संबंधित है।
4. साथ ही यह ईरान के पेट्रोलियम उत्पादों के देश में निरंतर आयात से भी जुड़ा हुआ है।

### भारत और इटली के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रम एवं रोजगार के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए भारत और इटली के बीच समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है। यह समझौता ज्ञापन निम्नलिखित के माध्यम से कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और शैक्षिक गतिविधियों के विस्तार में सहायता प्रदान करेगा:

1. प्रशिक्षण, कार्य-पद्धतियों और तकनीकियों के बारे में संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना;
2. विभिन्न सामाजिक भागीदारों के लिए नए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना;
3. श्रम रोजगार के बारे में विभिन्न विषयों में विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना;
4. प्रशिक्षण कार्य-पद्धतियों का मूल्यांकन करना;
5. विशेष रूप से श्रम प्रशासन के संदर्भ में, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में अच्छी कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान करना; प्रशिक्षण मॉड्यूल की आपूर्ति और सुविधा में एक-दूसरे की मदद करना तथा अध्ययन-भ्रमणों का आयोजन करना; और
6. ज्ञान और जानकारी साझा करने के लिए प्रशिक्षकों का आदान-प्रदान करना

### मुख्य प्रभाव

1. इस समझौता ज्ञापन का मुख्य प्रभाव कार्य के क्षेत्र में बदलाव से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने में दोनों संस्थानों की तकनीकी क्षमताओं का उन्नयन करने पर पड़ेगा।

2. यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को विकसित और आयोजित करने की तकनीकी क्षमताओं और **वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), नोएडा** के एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान के

#### पृष्ठभूमि

1. **वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई)** नोएडा, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, इसने और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी - आईएलओ), टूरिन ने 2012 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
2. इसने ज्ञान और अनुभव की आपसी साझेदारी के साथ अनेक गतिविधियों में सहायता प्रदान की। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य व्यावसायिक सहयोग जारी रखने के लिए संस्थानों के बीच सहयोग को औपचारिक रूप प्रदान करना है।
3. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) की स्थापना 1964 में टूरिन में हुई थी। तभी से यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम के विभिन्न आयामों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बिन्दु के रूप में कार्य कर रहा है।
4. आईटीसी रोजगार, श्रम, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता का व्यापक भंडार है।
5. आईटीसी का एक प्रमुख उद्देश्य श्रम और रोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षण गतिविधियों में नियोजित प्रमुख संस्थानों के साथ भागीदारी विकसित करना है।

रूप में क्रमिक विकास को बढ़ाएगा।

3. यह समझौता ज्ञापन समस्त एशिया प्रशांत क्षेत्र से सामाजिक भागीदारों के व्यापक क्षेत्र तक अपनी पहुंच का विस्तार करेगा।

### प्रथम विश्व युद्ध और दुनिया का नक्शा

दुनिया के इतिहास में करीब चार वर्षों तक चले प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। यह युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया। इस लड़ाई में दुनिया ने विनाश की उस तस्वीर को देखा जिसको दोबारा कोई नहीं देखना चाहेगा। इस लड़ाई में पांच करोड़ से अधिक लोगों की मौत हुई। इसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे तीन बड़े महाद्वीपों ने हिस्सा लिया और यह समुद्र से लेकर धरती और आकाश में लड़ा गया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें घायलों की ही संख्या करोड़ों में थी। इस विश्व युद्ध के खत्म होते-होते चार बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी (हैप्सबर्ग) और उस्मानिया ढह गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुईं और इसके अंत तक अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बनकर उभरा था।

क्या है

1. इस युद्ध में भारतीय जवान दुनिया में अलग-अलग मोर्चों पर लड़े थे। भारत के सिपाही फ्रांस और बेल्जियम, एडीन, अरब, पूर्वी अफ्रीका, गाली पोली, मिश्र, मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, पर्सिया और स्लोवाकिया समेत पूरे विश्व में विभिन्न लड़ाई के मैदानों में बड़े पराक्रम के साथ लड़े।
2. गढ़वाल राईफल्स रेजिमेंट के दो सिपाहियों को संयुक्त राज्य का उच्चतम पदक विक्टोरिया क्रॉस भी मिला था। हालांकि युद्ध के शुरुआती दौर में जर्मनी नहीं चाहता था कि भारत इसमें शामिल हो। इसकी बजाए वह भारत को ब्रिटेन के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहा था।
3. लेकिन इन सभी के उलट कांग्रेस इस लड़ाई में शामिल होने को लेकर ब्रिटेन को समर्थन दे रही थी। इस लड़ाई में कुल 8 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिसमें करीब 47746 सैनिक मारे गये और 65000 घायल हुए। इस युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर बेहद नकारात्मक प्रभाव हुआ और यह लगभग दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई।



### ऐसे हुई विश्व युद्ध की शुरुआत

1. इस युद्ध की शुरुआत 28 जून 1914, को सेराजेवो में ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्युक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या से हुई थी।
2. इसके एक माह के बाद आस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया था। इस काम में उसको रूस, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने मदद की।
3. जर्मनी ने फ्रांस की ओर बढ़ने से पूर्व तटस्थ बेल्जियम और लक्जमबर्ग पर हमला बोल दिया जिसके बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी।

### अमेरिका के शामिल होने की ये थी वजह

1. अगस्त 1917 के मध्य तक इस युद्ध में कई देश शामिल हो चुके थे। 1917 के बाद अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से इस युद्ध में शामिल हो गया था।
2. इस युद्ध में अमेरिका के कूदने की वजह जर्मनी द्वारा इंग्लैंड के लुसिटिनिया जहाज को डुबो देना थी।
3. इसमें कुछ अमेरिकी नागरिक सवार थे। इस घटना से गुस्साए अमेरिका ने भी ब्रिटेन की तरफ से इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी थी।
4. 1918 ई. में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर जर्मनी आदि राष्ट्रों को पराजित किया। जर्मनी और आस्ट्रिया की प्रार्थना पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई। लेकिन तब तक करोड़ों लोग इस युद्ध की वजह से अपनी जान गंवा चुके थे।

### भारत और मोरक्को में पारस्परिक सहायता करने पर सहमत

भारत और मोरक्को ने दीवानी एवं वाणिज्यिक अदालतों में पारस्परिक कानूनी सहायता और ज्यादा बढ़ाने से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए। केन्द्रीय विधि व न्याय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और मोरक्को में उनके समकक्ष न्याय मंत्री श्री मोहम्मद औज्जर इस अवसर पर उपस्थित थे। इस समझौते से सम्मन, न्यायिक दस्तावेजों, अनुरोध पत्रों और अदालती फरमान एवं पंच निर्णायक के पंचाट पर तामील में पारस्परिक सहयोग बढ़ेगा। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि भारत मोरक्को के साथ आपसी सहयोग का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता और इसके साथ ही दीवानी एवं वाणिज्यिक मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग के पहलुओं का विस्तार करने की सार्थकता को पूरा करने पर विश्वास करता है।

### क्या है

1. भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) और मोरक्को साम्राज्य के न्याय मंत्रालय के बीच आधुनिकीकरण के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के उपयोग के क्षेत्र में सहयोग संबंधी आशय के एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
2. इसका उद्देश्य एक साधन के रूप में आईटी का उपयोग कर अदालतों के आधुनिकीकरण सहित ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करना है, ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं या तौर-तरीकों के आदान-प्रदान, पदाधिकारियों एवं विशेषज्ञों के क्षेत्रीय दौरों और दोनों ही पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित अन्य साधनों के जरिए दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभान्वित हो सकें।
3. भारत सरकार के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंयूटिंग (सीडैक) ने मोरक्को के कांसाब्लांका में

### प्रस्तावित समझौते की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं

1. सम्मन और अन्य न्यायिक दस्तावेजों या प्रक्रियाओं पर तामील
2. दीवानी मामलों में साक्ष्य लेना
3. दस्तावेजों, रिकॉर्डिंग को प्रस्तुत पहचान और जांच करना
4. दीवानी मामलों में साक्ष्य लेने के लिए अनुरोध पत्र पर तामील
5. पंच निर्णायकों के पंचाट को स्वीकार एवं कार्यान्वित करना

- सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े एक उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की थी। इस केन्द्र का उद्घाटन 7 मई, 2018 को किया गया था। इसमें 193 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में पहले ही हो चुका है।
4. उपर्युक्त समझौता भारत और मोरक्को दोनों ही देशों के नागरिकों के लिए लाभप्रद साबित होगा। इस समझौते से दीवानी एवं वाणिज्यिक मामलों में मैत्रीपूर्ण एवं सार्थक सहयोग को मजबूत करने से संबंधित दोनों देशों की प्रबल इच्छा की भी पूर्ति होगी जो इस समझौते की मूल शैली, भावना एवं सार है।
  5. **भारत और मोरक्को ने 14वीं शताब्दी से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भों में बातचीत की है** जब टैंगियर के प्रसिद्ध यात्री एवं लेखक इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी।
  6. मध्ययुगीन भारतीय समाज पर उनके लेखन भारतीयों के साथ-साथ मोरक्को के नागरिकों के लिए भी **भारत से जुड़ी ऐतिहासिक सूचनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।**
  7. जहां तक आधुनिक इतिहास का सवाल है, भारत मोरक्को के स्वतंत्रता आंदोलन को अपनी ओर से संयुक्त राष्ट्र में समर्थन प्रदान करने में अत्यंत सक्रिय रहा था और इसके साथ ही भारत ने 20 जून, 1956 को उस समय मोरक्को को मान्यता प्रदान की थी जब वह फ्रांस के साथ की गई संरक्षित व्यवस्था से आजाद हो गया था। इसके साथ ही वर्ष 1957 में राजनयिक मिशन स्थापित किए गए थे।
  8. आपसी संबंधों के आगाज के समय से ही भारत और मोरक्को के बीच सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण रिश्ते कायम हैं। समय-समय पर भारत और मोरक्को के गणमान्य व्यक्ति एक-दूसरे के यहां दौरे पर जाते रहे हैं। मोरक्को का दौरा करने वाले भारत के गणमान्य व्यक्तियों में उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन (1967) और विधि एवं न्याय मंत्री (2016) शामिल हैं।

## अर्थशास्त्र

### भारत में निवेश के लिए चीन के बैंक ने बनाया कोष

चीन के सबसे बड़े बैंक इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चायना (आइसीबीसी) की भारतीय इकाई ने भारत के अत्यधिक संभावनाशील सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में निवेश करने के लिए 20 करोड़ डॉलर (1400 करोड़ रुपये) का कोष गठित किया है। चीन में भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि आइसीबीसी इंडिया के सीईओ डोंग बिन ने दूसरे स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टमेंट सेमिनार में इसकी घोषणा की। उन्होंने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम और उनमें निवेश के तरीके पर अपने विचार रखे। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के संभावनाशील एमएसएमई और वेंचरों में निवेश करने के लिए आइसीबीसी इंडिया ने 20 करोड़ डॉलर का एक कोष बनाया है।

### क्या है

1. **आइसीबीसी ने 2011 में मुंबई में अपनी शाखा स्थापित की थी।** भारतीय दूतावास के आर्थिक और वाणिज्य सलाहकार प्रशांत लोखंडे ने कहा कि भारतीय दूतावास, स्टार्टअप इंडिया एसोसिएशन (एसआइए) और वेंचर गुरुकूल द्वारा आयोजित सेमिनार में 350 से अधिक चीनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें अधिकतर चीन के वेंचर कैपिटल और एंजल निवेशकों के प्रतिनिधि थे। 20 भारतीय स्टार्टअप का प्रतिनिधित्व करने वाले 42 भारतीय उद्यमियों ने भी इसमें हिस्सा लिया।
2. केपीएमजी की 'इंडिया-चाइना: स्टार्टअप एंड बियॉड' शीर्षक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की कंपनियों ने 2017 में भारत के स्टार्टअप में दो अरब डॉलर (14000 करोड़ रुपये) से अधिक निवेश किया, जो इससे एक साल पहले के मुकाबले तीन गुना अधिक है।
3. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 के बाद से चीन की कंपनियों की ओर से निवेश में काफी बढ़ोतरी दिखी है। ये निवेश खासकर स्टार्टअप और तकनीक प्लेटफॉर्म में हो रहे हैं। सेमिनार में परामर्श कंपनी केपीएमजी ने 'इंडिया-चाइना: स्टार्टअप एंड बियॉड' शीर्षक से एक रिपोर्ट भी जारी की।

## डीआईपीपी 'ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट 2018' पर सम्मेलन की मेजबानी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) 14-15 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में 'ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट (जीडीसीएम) 2018' पर सम्मेलन की मेजबानी किया। इस सम्मेलन के दौरान संगीत, फिल्म, प्रसारण एवं प्रकाशन के साथ-साथ सामूहिक प्रबंधन, उभरते मॉडलों और बाजार व नीति निर्माताओं के लिए निहितार्थों पर भी विभिन्न सत्र आयोजित किए गए।

भारत में फिल्मों, संगीत और मीडिया से जुड़े रचनात्मक उद्योग की अत्यंत मजबूत पैठ को ध्यान में रखते हुए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (विपो) ने इस सम्मेलन के लिए भारत का चयन एक मेजबान देश के रूप में किया है। इस वर्ष आयोजित किए जा रहे सम्मेलन का फोकस एशिया-प्रशांत क्षेत्र है। 'जीडीसीएम 2018' में विश्व भर के विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों एवं डिजिटल उद्योग के प्रोफेशनल और संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न मिशनों से जुड़े राजनयिक समुदाय के प्रतिनिधिगण भी भाग लिया।

### क्या है

1. 'जीडीसीएम 2018' का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को एकजुट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना और फिल्मों, संगीत, गेमिंग एवं रचनात्मक उद्योग में उपलब्ध नए अवसरों के साथ-साथ अभिनव डिजिटल प्रौद्योगिकियों की बढ़ती हो रहे व्यापक बदलावों के कारण बदलते रचनात्मक परिवेश की वजह से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चाएं सुनिश्चित करना है।
2. यह उम्मीद की जा रही है कि 'जीडीसीएम 2018' के जरिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न राष्ट्रों के बीच ज्ञान, संस्कृति और अच्छी प्रथाओं अथवा तौर-तरीकों का आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा।
3. 'जीडीसीएम' महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और प्रकाशन, फिल्म, संगीत व गेमिंग सरीखे डिजिटल एवं आईपी सृजित करने वाले उद्योगों के विकास में तेजी लाने वाला एक अहम प्लेटफॉर्म है। ये सभी उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उल्लेखनीय योगदान करते हैं।
4. 'जीडीसीएम' में भारत की ओर से महत्वपूर्ण हितधारकों की मौजूदगी इसे वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थापित करेगी।

### फलैशबैक

1. 'जीडीसीएम 2018' इस सम्मेलन का दूसरा संस्करण है। प्रथम सम्मेलन वर्ष 2016 में जिनेवा में आयोजित किया गया था।
2. नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (विपो) के महानिदेशक श्री फ्रांसिस गुरी ने कहा कि विपो का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी रचनात्मक कलाकार निरंतर संरक्षित होता रहे और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेहतर पारिश्रमिक मिले।
3. उन्होंने राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 के जरिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के साथ एकीकरण के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की जिसके तहत भारत सरकार ने देश में एक ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रयास किए हैं जो बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के सृजन के लिए अनुकूल है।
4. इसके लिए संबंधित विषय पर देश के नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ आईपीआर पर अमल की व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।
5. डीआईपीपी के सचिव श्री रमेश अभिषेक ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी कि 'वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018' में भारत वर्ष 2015 की तुलना में 24 पायदान ऊपर चढ़कर अब 57वें पायदान पर पहुंच गया है।
6. उन्होंने कहा कि भारत मध्य एवं दक्षिण एशिया में शीर्ष रैंकिंग वाली अर्थव्यवस्था है और वह पिछले सात वर्षों से निरंतर अपनी प्रति व्यक्ति जीडीपी के सापेक्ष नवाचार के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

## सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम का अगला चरण आज से

धनतेरस ( 5 सितंबर ) के मौके पर सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम का अगला चरण शुरू हुआ है। धनतेरस के मौके पर सोना खरीदना शुभ भी माना जाता है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान के मुताबिक सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम 5 नवंबर से 9 नवंबर तक खुली रहेगी और इसके लिए 3,183 रुपए प्रति ग्राम की दर से रेट तय किया गया है। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि जो भी खरीदार इसकी ऑनलाइन खरीद करेंगे और उसका डिजिटल मोड में भुगतान करेंगे उन्हें 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट भी दी जाएगी। इस छूट के साथ उनके लिए स्वर्ण बांड का निर्गम मूल्य 3,133 रुपए प्रति ग्राम होगा।

क्या होता है एसजीबी?

1. एसजीबी में निवेशकों को गोल्ड में पैसा लगाने का मौका मिलता है लेकिन इसके लिए उन्हें फिजिकल फॉर्म में गोल्ड रखने की जरूरत नहीं होती।
2. स्कीम में निवेशकों को प्रति यूनिट गोल्ड में निवेश का मौका मिलता है, जिसकी कीमत इस बुलियन के बाजार मूल्य से जुड़ी होती है। बॉन्ड के मैच्योर होने पर इसे नकदी में भुनाया जा सकता है।
3. इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद सोने की भौतिक मांग में कमी लाना होता है। साथ ही इस गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के दौरान आपको टैक्स में भी छूट मिल सकती है।
4. गोल्ड बॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई ) जारी करता है।

## विज्ञान एवं तकनीकी

धरती की ओजोन परत दुरुस्त हो रही है

संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि धरती की सुरक्षात्मक ओजोन परत एयरोसॉल स्प्रै और शीतलकों ( कूलन्ट ) से हुए नुकसान से उबर रही है। ओजोन परत 1970 के दशक के बाद से महीन होती गई थी। वैज्ञानिकों ने इस खतरे के बारे में सूचित किया और ओजोन को कमजोर करने वाले रसायनों का धीरे धीरे पूरी दुनिया में इस्तेमाल खत्म किया गया।

क्या है

1. इक्वाडोर के क्विटो में 5 नवम्बर 2018 को हुए एक सम्मेलन में जारी किए गए वैज्ञानिक आकलन के मुताबिक, इसका परिणाम यह होगा कि 2030 तक उत्तरी गोलार्ध के ऊपर ओजोन की ऊपरी परत पूरी तरह दुरुस्त हो जाएगी।
2. अंटार्कटिक ओजोन छिद्र 2060 तक गायब हो जाना चाहिए। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रक्रिया कुछ धीमी है और उसकी ओजोन परत सदी के मध्य तक ठीक हो जाएगी।
3. नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के प्रमुख पृथ्वी वैज्ञानिक और रिपोर्ट के सह प्रमुख ने कहा, 'यह वाकई में बहुत अच्छी खबर है। अगर ओजोन को क्षीण बनाने वाले तत्व बढ़ते जाते तो हमें भयावह प्रभाव देखने को मिलते। हमने उसे रोक दिया।'
4. ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत है जो हमारे ग्रह को पराबैंगनी प्रकाश ( यूवी किरणों ) से बचाती है। पराबैंगनी किरणों त्वचा के कैंसर, फसलों को नुकसान और अन्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार होती है।

ऐसे होगी पूरी प्रक्रिया?

1. सबसे पहले गर्भवती महिला का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा।
2. इसके बाद महिला को डॉक्टरों की टीम के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।
3. अंतरिक्ष में महिला का प्रसव कराया जाएगा।
4. शिशु का डॉक्टरों की टीम मेडिकल चेकअप करेगी।
5. कुछ समय बिताने के बाद मां और शिशु को वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा।
6. यदि इंसानों को कई सारे ग्रहों पर रह सकने वाली प्रजाति बनानी है तो उन्हें अंतरिक्ष में प्रजनन की क्षमताओं को विकसित करना ही होगा- कीस मुल्डर, सीईओ, स्पेसलाइफ ओरिजिन।

## अंतरिक्ष में जन्म लेगा पहला इंसान

दूसरे ग्रह पर बसने की इंसान की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का एक और कदम करीब पहुंचने वाला है। इसी क्रम में 2024 में वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पहले इंसान का जन्म कराएंगे। तैयारियां जोरों पर हैं। नीदरलैंड की कंपनी स्पेसलाइफ ओरिजिन 36 घंटे के मिशन क्रेडल नामक अभियान में एक गर्भवती महिला को विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगी। इस महत्वाकांक्षी अभियान का मकसद अंतरिक्ष में मानव कॉलोनी बसाने का मंच तैयार करना है। इस अभियान के नतीजे अन्य ग्रह पर मानव प्रजनन की संभावनाओं को टटोलेंगे।

क्या है

1. 2024 तक अंतरिक्ष में पहले इंसान के पैदा होने से जुड़ा अभियान मिशन क्रेडल है। अन्य ग्रह पर बसने के लिहाज से इसे अहम अभियान माना जा रहा है। तभी तो दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे 'किसी शिशु का भले ही यह छोटा कदम हो, लेकिन मानवता के कल्याण के लिए विशाल शिशु कदम' मान रहे हैं।
2. इस अभियान के लिए 25 उन महिलाओं का चयन किया जाएगा जिनके गर्भधारण का समय एक दूसरे के आसपास होगा। इनमें से वह कोई एक महिला अंतरिक्ष में भेजी जाएगी जिसका प्रसव दो दिवसीय अभियान के दौरान होना एकदम सुनिश्चित होगा। महिलाओं का चयन 2022 में शुरू होगा।
3. कंपनी के सीईओ कीस मुल्डर का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को अंतरिक्ष में भेजने से पहले उनकी पूरी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। इसमें महिला और उसके गर्भ में पल रहे शिशु की पूरी चिकित्सकीय जांच की जाएगी। मिशन के दौरान गुरुत्वाकर्षण और खतरनाक विकिरण से महिला और उसके बच्चे को बचाने के पूरे इंतजाम होंगे।
4. मिशन क्रेडल की तरह ही मिशन लोटस पर भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इसके तहत 2021 में अंतरिक्ष में कृत्रिम मानव निषेचन कराया जाएगा।
5. धरती से महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु अंतरिक्ष भेजे जाएंगे। वहां इनका निषेचन कराया जाएगा। भ्रूण तैयार होने पर चार दिन बाद इसे वापस धरती पर लाया जाएगा।
6. इस अभियान में भी सामान्य गुरुत्व बरकरार रखा जाएगा जिससे कि भ्रूण को भारहीनता की स्थिति से न जूझना पड़े।

## साइबर हमलों के मामले में भारत

इंटरनेट सर्फिंग से जुड़े खतरों के मामले में भारत 12वें स्थान पर है। रूस की साइबर सिव्योरिटी फर्म कैस्पर्सकी लैब की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई से सितंबर के दौरान भारत में इंटरनेट प्रयोग करने वाले करीब तिहाई लोग साइबर हमलों का शिकार हुए।

क्या है

1. दक्षिण एशिया में कंपनी के जनरल मैनेजर श्रेणिक भयानी ने कहा, 'साइबर हमलों के पीछे मुख्य उद्देश्य पैसा ऐंठना होता है'।
2. इंटरनेट प्रयोग करने वालों की बढ़ती तादाद को ध्यान में रखते हुए भारत ऐसे खतरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। हमें ज्यादा जागरूक होने और बेहतर सुरक्षा की जरूरत है।
3. रिपोर्ट के अनुसार, हमलावर ज्यादातर ब्राउजर और उनके प्लग-इन के जरिये हमले को अंजाम देते हैं।
4. कई बार कुछ वेबसाइट को विजिट करते समय यूजर की जानकारी के बिना ही वायरस उनके कंप्यूटर में संध लगा देता है।
5. इसके अलावा किसी सर्वे के नाम पर भी अक्सर यूजर को बहकाकर वायरस वाली फाइल डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

## सोलर सिस्टम के करीब तक एलियंस पहुंचें

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऐस्ट्रोफिजिक्स सेंटर ने एलियंस और सोलर सिस्टम को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। स्टडी के अनुसार, एलियंस ने एक तरह से सोलर सिस्टम पर दस्तक दी है और इस संकेत में बड़े वैज्ञानिक रहस्य छुपे

हुए हैं। एलियंस के सोलर सिस्टम के बहुत नजदीक पहुंचने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद दो तारों के बीच के जगह में कृत्रिम प्रकाश की मौजूदगी है या फिर वहां जीवन से जुड़े कुछ संकेत हैं।

क्या है

1. वैज्ञानिकों का कहना है कि चट्टान जिसका नाम ओयुमुमुआ है जिसका अर्थ होता है कि आगमन के बाद का पहला संदेश होता है।
2. हवाई में दिखने के बाद सूर्य के स्टार सिस्टम में प्रवेश के साथ कुछ दूरसे संकेत मिले। से संकेत कृत्रिम तरीके से उत्पन्न हुए प्रकाश सेल की तरफ इशारा करते हैं। सूर्य की रेडिएशन की तरफ इन किरणों का झुकाव देखा गया।
3. सिंगार के आकार का यह छोटा तारा 400 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा जैसा नजर आया। 1,12,000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे इस ग्रह की गति को देखकर ऐसा लग रहा है कि वरुण ग्रह (नैपच्युन) को लगभग 4 साल पहले ही पार कर चुका है।
4. हालांकि, अभी तक इसने अपनी अधिकतम गति 3,13,600 किमी प्रति घंटे रिकार्ड किया गया है जब सितंबर में इसने सूर्य को पार किया था।

### भयंकर 'ट्रैफिक जाम' को अब मिटाएगा जापान

वाहनों की बढ़ती संख्या ने भारत की सड़कों पर जाम की समस्या खड़ी कर दी है। इस जाम से समय के साथ अरबों रुपये की हर साल बर्बादी हो रही है। भारत के शहरों से जाम खत्म करने के लिए अब जापान आगे आया है। भारत के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु से इसकी शुरुआत होने जा रही है। जापान और बेंगलुरु के बीच हुए समझौते के तहत वह इंटेलेजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम (आइटीएस) से भारत में ट्रैफिक जाम को खत्म करेगा। अगले साल मार्च में सिस्टम को लागू करने का काम शुरू हो जाएगा जो 2020 के मध्य तक चलेगा। इससे समस्या में 30 फीसद तक कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

क्या है

1. शहर में जाम लगने वाले 12 मुख्य स्थानों पर 72 सेंसर लगाए जाएंगे। कहां, कितना जाम लगा है जानने के लिए सार्वजनिक बसों पर जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) सेट किए जाएंगे।
2. ये डिटेक्टर अल्ट्रासॉनिक तरंगों के जरिए हर एक मिनट में ट्रैफिक की स्थिति सीधे ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर तक भेजेंगे जो हॉट स्पॉट के जरिए ट्रैफिक को अन्य मार्गों पर मोड़कर जाम हटाएगा।
3. 1.13 करोड़ डॉलर की इस परियोजना में जापान की अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआइसीए) निवेश करेगी। ये सरकारी संस्था विकासशील देशों को आर्थिक मदद देती है।
4. जापान में आइटीएस तकनीक 1990 से इस्तेमाल की जा रही है। श्रीलंका और कंबोडिया भी इस तकनीक से ही जाम की परेशानी से निपट रहे हैं। युगांडा भी इस पर काम कर रहा है।
5. 2017 में मास्को और रूस ने आइटीएस तकनीक से जाम की समस्या से 40 फीसद तक निजात पा ली है।
6. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दुनिया की कुछ शीर्ष सॉफ्टवेयर कंपनियां मौजूद हैं। 1920 तक ये गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता था।
7. पिछले तीन दशकों में टेक्नोलॉजी सेक्टर में आए उछाल ने शहर को टेक हब में बदल दिया और उसी दौरान यहां की जनसंख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई।

### साइबर हमले में भारत 21वें स्थान पर

विश्व पटल पर तकनीक के क्षेत्र में तेजी से उभरता भारत लंबे समय से साइबर अपराधियों का आसान लक्ष्य बना हुआ है। इस साल भी भारत सबसे ज्यादा साइबर हमले झेलने वाले देशों की सूची में 21वें स्थान पर है। हालांकि राहत की खबर ये है कि भारत की साइबर सुरक्षा दिन पर दिन मजबूत हो रही है। इसी साल भारत ने अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा



में पहली बार टॉप 10 देशों की सूची में नाम दर्ज कराया है। जानकारों का मानना है कि देश में साइबर लॉ की सख्ती, साइबर जागरूकता और साइबर सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर सक्रियता का असर जल्द ही दिखने लगेगा।

क्या है

1. इस साल की पहली छमाही में भारत पर कुल 6.95 लाख साइबर हमले हुए हैं। अकेले चीन, रूस, अमेरिका, नीदरलैंड और जर्मनी के साइबर अपराधियों ने भारत में कुल 4.3 लाख साइबर हमले किए हैं।
2. इस दौरान भारत को अपने देश में बैठे साइबर अपराधियों के भी 73 हजार से ज्यादा हमलों का सामना करना पड़ा। साइबर सुरक्षा से जुड़ी फिनलैंड की कंपनी एफ-सिक्वोर ने इसका खुलासा किया है।
3. कंपनी की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस की तरफ से सबसे ज्यादा 2,55,589 साइबर हमले हुए। अमेरिका में बैठे साइबर अपराधियों ने इस दौरान भारत में अपने लक्ष्य को 103,458 बार निशाना बनाया। चीन से 42,544, नीदरलैंड से 19,169 और जर्मनी से 15,330 साइबर हमले हुए।
4. साइबर हमलों का पता लगाने के लिए एफ-सिक्वोर ने दुनियाभर में 41 हनीपॉट स्थापित किए हैं। हनीपॉट एक तरह का सर्वर है, जो वास्तविक आइटी कंपनियों के सर्वर की तरह लगता है, लेकिन कंपनी ने इसे जानबूझकर कमजोर बनाया है ताकि साइबर अपराधी इसे आसानी से अपना लक्ष्य बनाएं।
5. इन हमलों से एक आंकड़ों के आधार पर कंपनी साइबर अपराधियों के लक्ष्यों, हमलों के तरीकों और तकनीक का विश्लेषण कर उससे बचाव के उपाय करती है।
6. एफ-सिक्वोर की रिपोर्ट के मुताबिक, साल की पहली छमाही के दौरान भारतीय हैकरों ने भी पांच देशों को अपना निशाना बनाया। भारतीय हैकरों की तरफ से ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, ब्रिटेन, जापान और उक्रेन में कुल 36,563 साइबर हमले किए गए।
7. साइबर हमलों के मामले में दुनिया में भारत का स्थान 21वां है। अपने ही देश में बैठे साइबर अपराधियों के हमलों के मामले में भारत 13वें स्थान पर है। अगर हम बात करें कि किस देश से दुनिया के विभिन्न देशों पर सबसे ज्यादा साइबर हमले हुए तो ब्रिटेन पहले स्थान पर आता है।
8. ब्रिटेन से 9.5 करोड़ से ज्यादा साइबर हमले किए गए। सबसे ज्यादा साइबर हमले झेलने वाले देशों में अमेरिका शीर्ष पर है। इस दौरान अमेरिका में एक करोड़ से ज्यादा साइबर हमले हुए।

अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा में भारत का आठवां स्थान

1. दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रतियोगिता 'कैप्चर द फ्लैग' में पहली बार भारत टॉप-10 में पहुंचा है। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 107 देशों की 2700 टीमों ने हिस्सा लिया था।
2. इनमें से 44 टीमों फाइनल में पहुंची थी। प्रतियोगिता में आइआइटी रुड़की की टीम भारत में अव्वल और विश्व स्तर पर आठवें स्थान पर रही। आइआइटी कानपुर में हुई इस प्रतियोगिता के अंतर्गत टीम के सदस्यों ने साइबर अटैक से लड़ने वाला सॉफ्टवेयर बनाया था, जिसका इस्तेमाल कर उन्होंने दिखाया। कई राउंड के बाद उन्हें विजयी घोषित किया गया।
3. इसी प्रतियोगिता में देश में दूसरे स्थान व विश्व स्तर पर 16वें स्थान पर आइआइटी इंदौर की टीम रही। देश में तीसरे व विश्व में 19वें स्थान पर इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली की टीम रही। इसके अलावा एप्लाइड रिसर्च प्रतियोगिता में आइआइटी मद्रास की टीम विजयी घोषित की गई। दूसरे स्थान पर आइआइटी गांधीनगर की टीम रही।
4. एंबेडेड सिक्वोरिटी चैलेंज में कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीम 'इंस्प्रा' देश में अव्वल रही। दूसरा स्थान आइआइटी खड़गपुर की टीम 'सील' ने प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर आइआइटी कानपुर की टीम रही।

सूर्य के निकटतम 'सुपर अर्थ'

खगोल विज्ञानियों ने सूर्य के निकटतम एकल तारे का चक्कर लगा रहे जमे हुए एक 'सुपर अर्थ' का पता लगाया है जिससे पृथ्वी के निकटतम पड़ोसी ग्रहों के बारे में जानकारियां सामने आ सकती हैं। ब्रिटेन के क्वीन मैरी

लंदन यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार संभवतः चट्टानों वाला यह ग्रह धरती से भी बड़ा है और उसे 'बर्नाड्स स्टार बी' के नाम से जाना जाता है।

**क्या है**

1. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह सुपर अर्थ अपने मेजबान तारे का 233 दिनों में चक्कर लगाता है। विज्ञान पत्रिका जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार यह ग्रह अपने मेजबान तारे से इतना दूर है जिसे 'स्नो लाइन' कहा जाता है। यानी इस दूरी पर पानी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजें ठंड की वजह से जम जाती हैं।
2. अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार, इस ग्रह की दशाएं पर्यावास क्षेत्र से परे हैं। पर्यावास क्षेत्र में द्रव पानी और संभवतः जीवन का अस्तित्व होता है।
3. इस ग्रह की सतह का तापमान शून्य से करीब 170 डिग्री सेल्सियस नीचे है। इसका मतलब है कि यह ऐसी जमी हुई दुनिया है जहां धरती जैसे जीवन के अनुकूल दशाएं नहीं हैं।

## विविध

### दुनिया के नंबर-1 पहलवान बने बजरंग पूनिया

स्टार भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने 10 नवम्बर 2018 को 65 किग्रा वर्ग में टॉप वर्ल्ड रैंकिंग हासिल की। इस सीजन में पांच पदक जीतने वाले 24 साल के बजरंग यूडब्ल्यूडब्ल्यू की लिस्ट में 96 अंक के साथ रैंकिंग में टॉप पर चल रहे हैं। इस साल उन्होंने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया था। बजरंग के लिए ये सीजन शानदार रहा और वो बुडापेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में वरीयता पाने वाले इकलौते भारतीय पहलवान रहे थे।

**क्या है**

1. बजरंग ने दूसरे स्थान पर मौजूद क्यूबा के एलेजांद्रो एनरिक व्लाडेस टोबियर पर मजबूत बढ़त बना रखी है जिनके 66 अंक हैं। बजरंग ने विश्व चैंपियनशिप के करीबी सेमीफाइनल में टोबियर को हराया था।
2. रूस के अखमद चाकेइव (62) तीसरे जबकि नए विश्व चैंपियन ताकुतो ओटोगुरो (56) चौथे स्थान पर हैं। इनके बाद तुर्की के सेलाहतिन किलिसाल्यान (50) का नंबर आता है।
3. बजरंग देश के इकलौते पुरुष पहलवान हैं जिन्हें रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह मिली है जबकि भारत की पांच महिला पहलवान अपने-अपने वर्ग में शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रही हैं।
4. विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले सिर्फ चौथी भारतीय महिला पहलवान बनी पूजा ढांडा महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में 52 अंक के साथ छठे स्थान पर हैं। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था।
5. रिनु फोगाट महिलाओं के 50 किग्रा वर्ग में 33 अंक के साथ 10वें स्थान पर हैं। सरिता मोर 59 किग्रा वर्ग में 29 अंक के साथ सातवें जबकि नवजोत कौर (32) और किरण (37) क्रमशः 68 और 76 किग्रा वर्ग में नौवें स्थान पर काबिज हैं।

### महिला टी-20 क्रिकेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय

कप्तान हरमनप्रीत के रिकार्ड शतक और युवा जेमिमा रोड्रिग्स के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से भारत ने न्यूजीलैंड को 34 रन से हराकर आईसीसी महिला विश्व टी20 में अपने अभियान का शानदार आगाज किया। हरमनप्रीत ने ग्रुप बी के इस मैच में छठे ओवर में क्रीज पर कदम रखा और 51 गेंदों पर 103 रन की लाजवाब पारी खेली जो इस प्रारूप में किसी भारतीय का पहला शतक है। उनकी पारी में सात चौके और आठ गगनदायी छक्के शामिल हैं। रोड्रिग्स ने 45 गेंदों पर सात चौकों की मदद से 59 रन बनाये जो उनका सर्वोच्च स्कोर है। इन दोनों ने चौथे विकेट के लिये 134 रन जोड़े जिससे टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाले भारत पांच विकेट पर 194 रन बनाये जो इस टूर्नामेंट का नया रिकार्ड है।

### क्या है

1. न्यूजीलैंड की टीम सूजी बेट्स की 50 गेंदों पर 67 रन की पारी के बावजूद नौ विकेट पर 160 रन ही बना सकी। कैटी मार्टिन ने भी 25 गेंदों पर 39 रन बनाये लेकिन इससे हार का अंतर ही कम हो पाया। अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय खेल रही दयालन हेमलता और पूनम यादव ने भारत की तरफ से तीन-तीन जबकि राधा यादव ने दो विकेट लिये।
2. हरमनप्रीत टी20 अंतरराष्ट्रीय में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बन गयी हैं। इससे पहले भारत की तरफ से सर्वाधिक स्कोर मिताली राज (नाबाद 97) के नाम पर था। यही नहीं हरमनप्रीत और रोड्रिग्स ने भारत के लिये पहली बार चौथे विकेट के लिये शतकीय साझेदारी निभायी। भारत ने विश्व टी20 में सर्वाधिक स्कोर भी बनाया। उसने आस्ट्रेलिया (चार विकेट 194 रन बनाम आयरलैंड, 2014) का रिकार्ड तोड़ा।

### एक देश-एक लाइसेंस की अधिसूचना जारी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक देश-एक लाइसेंस योजना वाली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जुलाई, 2019 से देशभर में एक जैसा ड्राइविंग लाइसेंस मिलने लगेगा। इस कार्ड में चालक की सूचनाएं सामने की तरफ और पीछे चिप में भी सेव होंगी। इस लाइसेंस में चालक का ब्लड ग्रुप, वो अंग दान कर सकता है की नहीं और लाइसेंस की वैधता को लेकर सूचना कार्ड के सामने वाले हिस्से में ही प्रिंट होगी।

### क्या है

1. मौजूदा प्रारूप में लाइसेंस पर इसे जारी करने वाले राज्य के विभाग का नाम लिखा होता है। इसकी वजह से किसी अन्य राज्य में चालक की पहचान करने में काफी दिक्कतें सामने आती हैं।
2. ड्राइविंग लाइसेंस के पिछले हिस्से में चिप मौजूद होगी, जिसका एक नंबर होगा। हर कार्ड के चिप का एक अलग नंबर होगा। अगर चालक के पास विशेष तरह के वाहन चलाने की योग्यता है तो उसकी जानकारी भी लाइसेंस पर मौजूद होगी।
3. इस हिस्से में क्यूआर कोड भी होगा जिसे ट्रैफिक पुलिस या एनफोर्समेंट एजेंसी स्कैन करके चालक की सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकती हैं।
4. वाहन चलाने के लिए अगर चालक ने बैज लिया हुआ है तो उसकी जानकारी लाइसेंस से मिल जाएगी। इस कार्ड पर आपात स्थिति में संपर्क करने के भी लिए नंबर उपलब्ध होगा।
5. कार्ड में सभी जानकारियां सेव होने से अधिकारी इसे कभी भी स्कैन कर सकेंगे, ऐसे में बार-बार नियम तोड़ने वाले को आसानी से पकड़ने में सहूलियत होगी।

### झरसुगुड़ा हवाई अड्डे का नाम बदला

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा के झरसुगुड़ा हवाई अड्डे का नया नाम 'वीर सुरेन्द्र साई हवाई अड्डा, झरसुगुड़ा' करने की स्वीकृति दे दी है।

### क्या है

1. वीर सुरेन्द्र साई ओडिशा के जाने-माने स्वतंत्रता सेनानी हैं।
2. झरसुगुड़ा हवाई अड्डे को नया नाम देने से ओडिशा सरकार की पुरानी मांग पूरी होगी जो स्थानीय लोगों की भावनाओं के अनुकूल है।
3. यह कदम राज्य से जुड़े सम्मानित लोगों के प्रति उचित श्रद्धांजलि भी होगा।

### एशिया में अभी भी भूख से जूझ रहे हैं

तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के बावजूद एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अभी भी करीब 50 करोड़ लोग भूख से जूझ रहे हैं क्योंकि खाद्य सुरक्षा और बुनियादी जीवन स्तर में सुधार संबंधी प्रगति थम सी गई है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी

एक रिपोर्ट में यह बात कही गयी है।

**क्या है**

1. **खाद्य एवं कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र की तीन अन्य एजेंसियों द्वारा संकलित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तुलनात्मक रूप से बेहतर शहरों जैसे बैंकॉक और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में भी गरीब परिवार अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना नहीं जुटा पाते हैं। इसका उनके स्वास्थ्य और भविष्य में उत्पादकता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।**
2. बैंकॉक में 2017 में एक तिहाई से ज्यादा बच्चों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा था।
3. रिपोर्ट में एक सरकारी सर्वेक्षण के हवाले से कहा गया है कि **पाकिस्तान में महज चार फीसदी बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य भोजन मिल रहा है।**

### 1971 के युद्ध के हीरो का निधन

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाने वाले वाइस एडमिरल (सेवानिवृत्त) एमपी अवाति (93) का महाराष्ट्र के सतारा जिले में निधन हो गया। **वीर चक्र से सम्मानित अवाति के निधन पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दुख जताते हुए उन्हें नौसेना के इतिहास का आइकन बताया। नौसेना प्रमुख सुनील लांबा ने उनके निधन को एक युग का खत्म होना बताया।**

**क्या है**

1. इस युद्ध के दौरान अवाति नौसेना के पूर्वी बेड़े का नेतृत्व कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, 'वीर चक्र से सम्मानित अवाति अब नहीं रहे'।
2. वह 1971 युद्ध के दौरान पूर्वी बेड़े के कमांडिंग आफिसर थे। उन्होंने प्रतिबंधित सामान ले जा रहे दुश्मनों के तीन जहाजों को पकड़ा था।
3. उनके नेतृत्व में ही दुश्मनों की पनडुब्बी को नष्ट किया गया था। वह नौसेना इतिहास के आइकन थे। उनके निधन पर देश श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

### वूमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2018

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 10 दिवसीय "वूमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2018" का पांचवा संस्करण 4 नवंबर, 2018 की रात्रि में समाप्त हुआ। इसे जनपथ स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया गया था। इन 10 दिनों में पूरे देश से आई महिला किसानों और उद्यमियों ने विभिन्न किस्मों के जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया। इसमें **खाद्य पदार्थ से लेकर वस्त्र, स्वास्थ्य व सौन्दर्य प्रसाधन आदि शामिल थे।**

**क्या है**

1. **26 राज्यों से आए महिला किसानों एवं उद्यमियों ने इस वर्ष 2.75 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिक्री की। पिछले वर्ष यह फेस्टिवल दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जहां उत्पादों की बिक्री 1.84 करोड़ रुपये की रही थी। रिकॉर्ड 12 लाख लोग इस प्रदर्शनी को देखने आए।**
2. इस आयोजन की सफलता ने मजूली, कांगड़ा, लेह, पलक्कड, चिकमंगलूर, यवतमाल, दीमापुर, अलमोड़ा आदि जगहों से आए महिला किसानों को उत्साहित किया है। कार्यक्रम के दौरान महिला किसानों व उद्यमियों को यात्रा करने तथा दिल्ली में ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष वेजन फूड का स्टॉक लगाया गया था जिसे आगंतुकों ने बहुत पसंद किया।
3. **वूमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2018 का उदघाटन 26 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी द्वारा किया गया था।**
4. मुंबई की महिला उद्यमी सुश्री अनामिका ने बांस के टूथब्रश और स्टील के स्ट्रॉ का प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि लोगों की प्रतिक्रियाएं उत्साहवर्धक है। पंजाब की महिला किसान सुश्री सरबजीत कौर ने कहा कि वे पहली बार यहां

आई हैं और विभिन्न किस्मों के जैविक अनाजों के प्रति लोगों के रुझान को देखकर प्रसन्न है। उन्होंने ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए महिला व बाल विकास मंत्रालय को धन्यवाद दिया। तमिलनाडु से आई सुश्री अपर्णा के स्टॉल में चावल की 30 से ज्यादा किस्में थी जिसे तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, ओडिशा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल राज्यों से संग्रह किया गया था। मणिपुर के चखाओ पोईरीटन तथा पश्चिम बंगाल के गोविंद भोग चावल को लोगों ने बहुत पसंद किया।

5. वूमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2018 के प्रतिनिधियों को महिला ई-हाट में पंजीकरण का अवसर दिया गया है। इस पोर्टल का निर्माण महिला व बाल विकास मंत्रालय ने किया है। यह पोर्टल, फेस्टिवल, 2018 के बाद भी महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता प्रदान करेगा।

### कुंभ से पहले एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग

गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के तट पर बसे प्रयागराज को अगले साल 15 जनवरी से शुरू होने जा रहे कुंभ मेले से पहले एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग मिल सकती है। यह देश की सबसे तेजी से बनने वाली एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे रिकार्ड 11 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

क्या है

1. एएआई एयरपोर्ट पर और ज्यादा विमानों को खड़ा करने की सुविधा तैयार कर रहा है जो पहले की योजना से अधिक है। एएआई के चेयरमैन गुरुप्रसाद महापात्रा ने कहा, 'चूंकि प्रयागराज को देश के अन्य राज्यों से जोड़ने की मांग काफी ज्यादा हो रही है, हम और ज्यादा विमानों को खड़ा करने के लिए पार्किंग एरिया बना रहे हैं।
2. इसके लिए पहले बनी योजना में बदलाव किया गया है। अतिरिक्त पार्किंग एरिया बनाने पर 40 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, बड़ी संख्या में लोग यहां पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं और लाखों छात्र पढ़ाई करते हैं, इसलिए इस शहर को जोड़ने वाली हवाई सेवा को सुधारने के लिए लगातार मांग उठ रही है।
3. कुछ महीने पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यसनाथ ने एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान इस टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था।

### दीवाली पर ARMY को खास उपहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौ नवंबर को सेना को बड़ी सौगात देंगे। आर्टिलरी की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय सेना को तीन एम-777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप और तीन बख्तरबंद तोप के-9 वज्र बख्तरबंद तोप नौ नवंबर को मिल जाएंगी। महाराष्ट्र के नासिक स्थित देवलाली में होने वाले एक भव्य समारोह में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहेंगे। बोफोर्स के बाद 31 सालों में भारतीय सेना को यह पहली तोप मिलेगी। के-9 वज्र को साउथ कोरिया की कंपनी हनवहा टेक विन ने मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया है। भारत में इस बख्तरबंद तोप का निर्माण एलएंडटी करेगी। वर्ष 2020 तक 100 के-9 वज्र आर्टिलरी तोप भारतीय सेना के पास होंगी।

क्या है

1. कुल 4500 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के तहत सेना को 10 तैयार तोपें मिलेंगी, जबकि 90 का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत होगा। यह तोप तीन सेकेंड में तीन गोले दागने में सक्षम है।
2. न्यूक्लियर वारफेयर केमिकल से निपटने के लिए सीबीआरएन तकनीक से यह तोप लैस है। यह बख्तरबंद तोप 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से दौड़ सकती है। तो रेगिस्तानी इलाकों में भी चल सकती है। इस वजह से यह तोप भारत पाक की राजस्थान और पंजाब सीमा पर बहुत प्रभावी होगी।
3. के-9 वज्र बख्तरबंद तोप को चलाने के लिए इसके अंदर पांच जवान होते हैं। यह अचूक 39 किमी. तक दुश्मन को मिटाने की काबिलियत रखती है। इस तोप का कैलिबर 155 एमएम का है। इसका गोला जहां भी गिरेगा वहां 50 मीटर तक तबाही मचा देगा। यह तोप दिन और रात में कभी भी फायर करने में सक्षम है।

4. **एम 777 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोप है।** यह प्रोजेक्ट पांच हजार करोड़ रुपये का है। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजीमेंट में वर्ष 2021 तक कुल 145 एम-777 अल्ट्रालाइट होवित्जर शामिल होंगे।
5. **इसका वजन केवल 4.2 टन है।** इसलिए इसे चीनूक हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमान से हाई एल्टीट्यूट और दूसरी एरिया में तैनात किया जा सकता है।
6. कारगिल युद्ध के बाद सबसे ज्यादा कमी हाई एल्टीट्यूट वारफेयर की थी। यह तोप 31 किमी तक एक मिनट में चार राउंड फायर कर सकता है। इसका गोला 45 किलो का है। यह 155/39 एमएम की तोप है। इसे चलाने के लिए आठ जवान तैनात होंगे।

### दिव्यांग युवाओं के लिए वैश्विक आईटी प्रतिस्पर्धा में पुरस्कार

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिव्यांग युवाओं के लिए वैश्विक आईटी प्रतिस्पर्धा 2018 का समापन हुआ। 9-11 नवंबर, 2018 तक इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने रिहैबिलिटेशन इंटरनेशनल (आरआई), कोरिया और उनके सहयोगी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से किया है। श्री थावरचंद गहलोत और कोरिया, भारत और ईएससीएपी के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पुरस्कार प्रदान किए।

**क्या है**

1. **इस वर्ष 18 देशों** - भारत, इंडोनेशिया, चीन, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मंगोलिया, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात से आए 96 दिव्यांग युवाओं (दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर, अक्षमता और बौद्धिक अक्षमता/अवरूद्ध शारीरिक विकास) ने “दिव्यांग युवाओं के लिए वैश्विक आईटी प्रतिस्पर्धा 2018” में भाग लिया।
2. **ई-टूल और ई-लाइफ मैपिंग पर आधारित व्यक्तिगत स्पर्धा 9 नवंबर, 2018 को आयोजित की गई थी** और सामूहिक प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम 10 नवंबर, 2018 को पूरा हो गया था। साथ ही, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए आईसीटी के इस्तेमाल के बारे में विभिन्न भागीदार देशों द्वारा अपनाए जा रहे श्रेष्ठ क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए आईटी फोरम नामक एक अन्य कार्यक्रम में आईटी चुनौती प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई।
3. इस कार्यक्रम में श्रेष्ठ स्वयंसेवी पुरस्कारों सहित **विभिन्न श्रेणियों में 55 पुरस्कार प्रदान किए गए।** प्रत्येक श्रेणी यानी दृष्टि, श्रवण, शारीरिक एवं विकास/बौद्धिक अक्षमता में व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यक्रमों में “सर्वश्रेष्ठ, विशिष्ट और उत्तम” नामक तीन पुरस्कार प्रदान किए गए।
4. **थाइलैंड ने सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीते, उसके बाद 5 पुरस्कारों के साथ फिलीपींस को स्थान मिला। भारत ने सुपर चैलेंजर पुरस्कारों सहित 3 पुरस्कार जीते।** भारत से श्री मनजोत सिंह ने दृष्टि अक्षमता श्रेणी के तहत ई-टूल चैलेंज और ई-लाइफ चैलेंज में दो पुरस्कार जीते। साथ ही, भारत के श्री सौरव कुमार सिन्हा ने सुपर चैलेंजर पुरस्कार जीता।
5. **इंडोनेशिया की सुश्री फ़ैयजा पुत्री और अदिला ने ‘ग्लोबल आईटी लीडर पुरस्कार’ जीते।**
6. दिव्यांग युवाओं के लिए वैश्विक आईसीटी चैलेंज के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आईटी की मदद से दिव्यांगों का कौशल विकास करना है ताकि वह अपनी कमियों पर विजय पा सकें और इस तरह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बसने वाले सभी दिव्यांगजन समाज में अपनी सहभागिता बढ़ाने और अपना जीवन स्तर सुधारने में कामयाब हो सकें।
7. यह एक ऐसी क्षमता निर्माण परियोजना है, जो दिव्यांग युवाओं को आईसीटी और संबंधित क्रियाकलापों तक उनकी पहुंच कायम कराते हुए एक बेहतर भविष्य के लिए उनकी सीमाओं और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में उनकी मदद करती है।
8. इसके साथ ही विकलांगताओं से संबंधित भागीदार देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए आईसीटी एजेंडा निर्धारित करते समय जानकारी और सामाजिक भागीदारी से लैस करने में मदद मिलेगी।



9. भारत की ओर से इस प्रतिस्पर्धा के लिए 12 दिव्यांग युवाओं को नामित किया गया था। इनका चयन मंत्रालय द्वारा जून 2018 में कुरुक्षेत्र में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के जरिए किया गया था। भारत इस तरह की वैश्विक प्रतियोगिता में 2013 से ही हिस्सा ले रहा है और तब से यह पुरस्कार जीतता रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन पिछले साल वियतनाम में हुआ था।

### राष्ट्रीय दुग्ध गुणवत्ता सर्वे

देश में दूध काफी हद तक सुरक्षित है, लेकिन इसकी गुणवत्ता का मसला कायम है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने 13 नवम्बर 2018 को 'राष्ट्रीय दुग्ध गुणवत्ता सर्वे 2018' की अंतरिम रिपोर्ट जारी की। नमूनों (6,432) और मानकों के आधार पर अब तक का यह सबसे बड़ा अध्ययन बताया जा रहा है। एफएसएसएआइ के सीईओ पवन अग्रवाल ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि अध्ययन के दौरान केवल 10 फीसद यानी 638 नमूनों में मिलावट पाई गई। 90 प्रतिशत नमूने सुरक्षित पाए गए। उन्होंने कहा कि भारत में दूध काफी हद तक मिलावट से मुक्त है। 6,432 नमूनों में केवल 12 में ही खतरनाक स्तर की मिलावट पाई गई। हालांकि, इतने बड़े सर्वे में ये आंकड़े उल्लेखनीय महत्व नहीं रखते।

#### क्या है

1. सर्वे के दौरान दूध में 13 तरह की मिलावट की जांच की गई। इसमें वनस्पति तेल, डिटर्जेंट, ग्लूकोज, यूरिया और अमोनियम सल्फेट शामिल हैं।
2. दूध के नमूनों में एंटीबायोटिक अवशेष, कीटनाशक अवशेष और एफ्लैटॉक्सिन एम-1 की मिलावट की भी जांच की गई। हालांकि, एफएसएसएआइ के सीईओ ने यह नहीं बताया कि देश के किस हिस्से से लिए गए नमूनों में खतरनाक मिलावट पाई गई।
3. सर्वे में यह तथ्य भी सामने आया कि दूध में वसा (फैट) और ठोस गैर वसा (एसएनएफ) मानक के अनुरूप नहीं हैं। ऐसा उन्हीं नमूनों में पाया गया जो सीधे दूधवालों से लिए गए। प्रसंस्करित दूध अपेक्षाकृत सही पाया गया। हालांकि, प्रसंस्करित दूध में भले ही दूधवालों के मुकाबले गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा हो, लेकिन उसका स्तर संतोषजनक नहीं है।
4. कीटनाशक अवशेष को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक अवशेष के मामले में केवल 1.2 फीसद नमूने फेल हुए। इसकी वजह भी पशुओं के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली आक्सी-टेट्रासाइक्लिन है।

### भारत-ब्रिटेन मिलकर खोजेंगे कैंसर का सस्ता इलाज

कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। मरीज को कैंसर से पहले उसका इलाज मार डालता है। इसलिए भारत और ब्रिटेन मिलकर कैंसर का किफायती इलाज तलाश करने के लिए एक बड़े शोध कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ समय पूर्व दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर सहमति हुई थी। अब 14 नवम्बर 2018 को दोनों देशों के वैज्ञानिक शोध संस्थान इस कार्यक्रम पर समझौता करने जा रहे हैं। इसके बाद इस पर अमल शुरू होगा।

#### क्या है

1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत-ब्रिटेन कैंसर अनुसंधान पहल के नाम से यह कार्यक्रम अभी पांच सालों के लिए शुरू किया जाएगा।
2. इसमें भारत की तरफ से जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ब्रिटेन की तरफ से प्रतिष्ठित कैंसर रिसर्च यूके एजेंसी शामिल होगी। एमओयू भी इन्हीं दो संस्थानों के बीच होगा। दोनों संस्थान शोध के लिए 50-50 लाख पौंड की राशि प्रदान करेंगे।
3. इस शोध का मुख्य मकसद कैंसर का किफायती उपचार खोजना है। ताकि उपचार हर कैंसर पीड़ित के पहुंच में हो। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 18 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन यात्रा पर गए थे तो दोनों देशों में इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी तथा बाद में एक संयुक्त बयान जारी हुआ था।

### भारत में कैंसर के आंकड़ें

1. भारत में कैंसर रोगियों की संख्या 25 लाख के आसपास है।
2. कैंसर के 7 लाख नए मरीज हर साल आते हैं।
3. कैंसर से 71% मौतें 30 से 69 साल की आयु के बीच होती है।
4. देश में मुख एवं फेफड़ों के कैंसर और महिलाओं में स्तन कैंसर से होने वाली मृत्यु सभी कैंसर संबंधित मौत में 50% है।
5. भारत में बच्चेदानी के मुख के कैंसर की वजह से 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु होती है।

### इलाज की संभावनाएं

1. 90% से ज्यादा कैंसर मरीजों का प्रथम चरण में उपचार हो सकता है।
2. 70% मरीजों का सेकंड स्टेज में भी उपचार संभव है।
3. 40 फीसदी मरीजों का तीसरे चरण में इलाज संभव है।
4. 10 फीसदी उपचार की संभावना रहती है चौथे चरण में

### बीमारी पर खर्च

1. कैंसर बीमारी का ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) की अर्थव्यवस्था पर 46.3 अरब डॉलर का आर्थिक बोझ पड़ा है।
2. 2012 तक तंबाकू जनित उत्पादों से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट। (ब्रिक्स के सर्वे के मुताबिक)

### तंबाकू बड़ा कारक

1. देश में हर साल तंबाकू उत्पादों के सेवन से 10 लाख मौतें होती हैं
2. हर रोज तंबाकू से संबंधित रोगों के कारण 2500 व्यक्तियों की मौत हो जाती है
3. मुंह के कैंसर के मामलों में 90 फीसदी तंबाकू उत्पाद जिम्मेदार हैं।
4. भारत में 26.7 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं
5. 23 सितंबर 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने टिक्स पैक में तंबाकू जनित पदार्थों (गुटका, जर्दा, पान मसाला, खैनी इत्यादि) की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

### तमिलनाडु में 'गाजा' नहीं, आने वाला है 'गज'

बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवाती तूफान गाजा, 15 नवम्बर 2018 को 100 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में आया। भारत में इसके खतरे और इसे लेकर जारी की गई चेतावनियों के बारे में आप शायद जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि गाजा का मतलब क्या और कौन इन खतरनाक तूफानों को तितली, कटरीना, हुदहुद, नरगिस, नीना जैसे नाम कौन देता? इन तूफानों को नाम देने की वजह क्या है?

### क्या है

1. 'गाजा' तूफान का नाम संस्कृत के शब्द गज से बना है, जिसका मतलब होता है हाथी। इस चक्रवाती तूफान को ये नाम श्रीलंका के वैज्ञानिकों ने दिया है। मालूम हो कि श्रीलंका में हाथियों की अच्छी तादात है और वहां उन्हें काफी सम्मान के तौर पर देखा जाता है।
2. श्रीलंका के रईस लोगों में इन दिनों हाथियों के बच्चे पालने का भी एक नया चलन शुरू हो चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इस तूफान का नाम 'गाजा' रखा है।
3. अलग-अलग रीजन में उठने वाले तूफानों को अलग-अलग चेतावनी केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा नाम दिया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि वैज्ञानिकों, आम जनता और चेतावनी केंद्रों के बीच संचार में सुविधा हो और किसी तरह की गलतफहमी न हो।

4. सामान्यतः भविष्य में आने वाले तूफानों के नाम पहले ही रख कर उनकी सूची तैयार कर ली जाती है। जैसे 'गाजा' के बाद अगला तूफान 'फेथाई' होगा। इसका नामकरण थाईलैंड के वैज्ञानिकों ने किया है। इस तूफान के भी इस वर्ष के अंत तक आने की आशंका है।
5. दुनिया भर में चक्रवातों के नाम रखने की शुरुआत 1953 से हुई। इसके पहले इस अवधारणा का विकास नहीं हुआ था। 1953 से वर्ल्ड मेटेोरियोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन ( डब्ल्यूएमओ ) और मायामी नेशनल हरीकेन सेंटर ने चक्रवातों के नाम रखने की परंपरा शुरू की।
6. डब्ल्यूएमओ जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। डब्ल्यूएमओ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आने वाले चक्रवातों के नाम रखता आया है। लेकिन 2004 में डब्ल्यूएमओ की अगुवाई वाली अंतरराष्ट्रीय पैनल को भंग कर दिया गया। इसके बाद सभी देशों से अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले चक्रवात का नाम खुद रखने को कहा गया।

#### उत्तरी हिंद महासागर में बाद में शुरू हुई ये पहल

1. पहले उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का कोई नाम नहीं रखा जाता था। जानकारों के मुताबिक इसकी वजह यह थी कि सांस्कृतिक विविधता वाले इस क्षेत्र में ऐसा करते हुए बेहद सावधानी की जरूरत थी ताकि लोगों की भावनाएं आहत होने से कोई विवाद खड़ा न हो।
2. लेकिन बाद में हिंद महासागर क्षेत्र के आठ देशों ने भारत की पहल पर चक्रवातीय तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू की। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड को मिलाकर कुल आठ देश शामिल हैं।
3. हिंद महासागर क्षेत्र के आठ देशों ने भारत की पहल पर चक्रवात को नाम देने की व्यवस्था शुरू की। इन देशों के मौसम वैज्ञानिकों ने 64 नामों की सूची बनाई है।
4. हर देश की तरफ से आठ नाम इसमें शामिल किए गए हैं। पिछली बार भारी तबाही मचाने वाले तूफान 'तितली' का नामकरण पाकिस्तान ने किया था।
5. 'तितली' के बाद आने वाले तूफान का नाम 'लोबान' रखा गया था, जो ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया है।
6. 'लुबान' के आसपास ही आए चक्रवाती तूफान का नाम 'दाए' था, जो म्यांमार के मौसम वैज्ञानिकों ने रखा था। अब बारी श्रीलंका की थी, लिहाजा उनके प्रस्तावित नाम के अनुसार मौजूदा तूफान का नाम गाजा रखा गया है।

#### इतनी सावधानी के बावजूद विवाद

1. साल 2013 में 'महासेन' तूफान को लेकर आपत्ति जताई गई थी। श्रीलंका द्वारा रखे गए इस नाम पर इसी देश के कुछ वर्गों और अधिकारियों को ऐतराज था। उनके मुताबिक राजा महासेन श्रीलंका में शांति और समृद्धि लाए थे, इसलिए आपदा का नाम उनके नाम पर रखना गलत है। इसके बाद इस तूफान का नाम बदलकर 'वियारु' कर दिया गया।
2. तूफानों और चक्रवातों के नाम महिलाओं के नाम पर ही क्यों? इसे लेकर भी विवाद हो चुका है, जिसके बाद तूफानों के नाम पुरुषों के नाम पर भी रखने शुरू किए गए।
3. वेस्टइंडीज के निवासी तूफानों और चक्रवातों के नाम, अपने किसी संत के नाम पर रखते रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे भारत में रेनबो को हिंदू देवताओं के मुखिया इंद्र से जोड़ते हुए इंद्रधनुष कहते रहे हैं।
4. नाम को लेकर विवाद में ईवान आर. तन्नेहिल की किताब 'हरीकेंस' में पता चला कि आस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञानी क्लीमेंट रैगी ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के महिला नाम रखने का सिलसिला शुरू किया था।
5. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तो तूफानों के महिला नामकरण की अवधारणा इतनी तेज हुई कि इसके खिलाफ कई नारीवादियों ने नाराजगी जाहिर की। 50, 60 और 70 के दशक में इस मसले को घोर लैंगिक पूर्वाग्रह और नारी अपमान से जोड़कर प्रमुखता से उठाया गया।
6. उस समय की प्रखर नारीवादी रॉक्सी बोल्टन ने मौसम सेवा को एक आपत्तिनामा भेजकर पूछा, 'क्या महिलाएं जीवन और समाज के लिए नाशक हैं? क्या महिलाएं तूफान की तरह ही तबाही लाती हैं?' बोल्टन ने अमेरिकी संसद के पुरुष सदस्यों और मंत्रियों के नाम पर चक्रवातों के नामकरण की वकालत की। ताकि पुरुषों को महिला समाज का अपमान

- समझ में आए। उनकी आवाज में जब हजारों लोगों की आवाज मिली तो 1979 में पुरुष तूफानों का जन्म हुआ। फिर पुरुषों के नाम से भी तूफानों के नाम रखे जाने लगे। पर अभी भी महिला तूफानों के नाम कहीं ज्यादा हैं।
7. हाल ही में इलिनॉय यूनिवर्सिटी के एक शोध में यहां तक बता दिया गया कि महिला तूफान पुरुष तूफानों से तीन गुना खतरनाक होते हैं। नारीवादियों ने इस पर घोर आपत्ति जताई थी।
  8. 'एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हरीकेन, टायफून एंड साइक्लोन' में लिखा गया है, 'तूफानों के अप्रत्याशित व्यवहार और चरित्र के कारण उनका नामकरण महिलाओं के नाम पर किया जाता रहा है'। नारीवादियों का तर्क है कि जो पैल ऐसे नाम रखते हैं, उनमें मर्दों का वर्चस्व है।

## विश्व एंटीबायोटिक्स जागरूकता सप्ताह

एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल पूरी दुनिया में बड़ा खतरा बनता जा रहा है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह मनाता है। 12 से 18 नवंबर 2018 तक चलने वाले इस जागरूकता सप्ताह का मकसद लोगों को एंटीबायोटिक दवाओं के साइड इफेक्ट के प्रति जागरूक करना है। एक रिपोर्ट के अनुसार एंटी बायोटिक्स अमेरिका के लिए सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में भी एंटीबायोटिक्स दवाओं का गलत इस्तेमाल गंभीर समस्या का रूप लेता जा रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि एंटीबायोटिक दवाओं का सही प्रयोग न केवल क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल संक्रमण और एंटीबायोटिक प्रतिरोध की दरों को कम करने में मदद करता है, बल्कि इलाज की लागत को कम करने के दौरान रोगी के चिकित्सा परिणामों में भी सुधार कर सकता है। WHO के मुताबिक एंटीबायोटिक दवाएं, वायरस संक्रमण को रोकने और इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध तब होता है, जब इन दवाओं के उपयोग के जवाब में बैक्टीरिया अपना स्वरूप बदल लेता है।

ये है एंटीबायोटिक का खतरा

1. एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से बैक्टीरिया प्रतिरोधी बन जाते हैं। ये बैक्टीरिया मनुष्यों और जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं। गैर-प्रतिरोधी बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण से उनका इलाज कठिन हो जाता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध, इसके दुरुपयोग और बहुत ज्यादा उपयोग से भी तेज होता है।
2. एंटीबायोटिक दवाओं के गलत इस्तेमाल का ही नतीजा है कि ये अब पूरी दुनिया में जीवाणुओं पर बेअसर साबित हो रही हैं। प्रतिरोधक क्षमता हासिल

### फ्लैशबैक

1. पहली एंटीबायोटिक, पेनसिलिन की खोज वर्ष 1928 में हुई थी। इसके बाद से अब तक तकरीबन 51 एंटीबायोटिक्स दवाओं की खोज हो चुकी है। इनका 5 से 15 दिन का कोर्स होता है, जिसे पूरा करना जरूरी होता है। कोर्स पूरा न करने पर संक्रामक बीमारी और खतरनाक हो सकती है।
2. WHO ने एंटीबायोटिक दवा के इस्तेमाल के लिए प्रोटोकाल तैयार किया है। इसके अनुसार मरीज के शरीर में बैक्टीरिया संक्रमण की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए। बिना जांच के एंटीबायोटिक लेने पर उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं।
3. इन्फेक्शन, दर्द और मौत के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया को खत्म करने में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल होता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। पेट की समस्या इनमें आम है।
4. एंटीबायोटिक्स संग प्रोबायोटिक्स लेने से साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं।
5. प्रोबायोटिक्स कुछ साल पहले लॉन्च हुई है। ऐसे में इनका कितना और किस तरह का फायदा या नुकसान होता है, इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। ऐसे में लंबे समय तक चलने वाली और ऐसी एंटीबायोटिक्स, जिनसे साइड इफेक्ट होना तय है संग ही प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं।
6. फिलहाल प्रोबायोटिक्स, कैप्सूल व पेय पदार्थ की फॉर्म में आ रहे हैं।
7. दही एक अच्छा प्रोबायोटिक्स है। अगर आप खाने में नियमित रूप से दही का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत अच्छा है।

- कर चुके इन जीवाणुओं को निष्क्रिय करने के लिए नई एंटीबायोटिक दवाएं विकसित नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में असरदार एंटीबायोटिक का संकट पैदा हो गया है।
3. यह समस्या इतनी गंभीर है कि पिछले वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस बारे में अलर्ट जारी करना पड़ा था। रिपोर्ट के अनुसार, अभी दुनिया में कुल 51 एंटीबायोटिक दवाओं पर काम चल रहा है। मगर, डब्ल्यूएचओ का मानना है कि इनमें से आठ ही नई हैं, इसलिए इन आठ दवाओं पर ही उम्मीद टिकी है।
  4. WHO ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ पैदा हो रही प्रतिरोधक क्षमता के कारण आने वाले समय में दुनिया भर में होने वाली मौतों की संख्या काफी बढ़ सकती है। एंटीबायोटिक को लेकर एक और समस्या यह है कि एंटीबायोटिक दवाओं को विकसित करने में काफी खर्च होता है। गौरतलब है कि अभी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से दुनियाभर में सात लाख मौतें सालाना होती हैं।
  5. कहा जा रहा है कि साल 2050 तक यह आंकड़ा बढ़कर एक करोड़ तक हो सकता है। भारत के बारे में अलग से आंकड़ा नहीं है। लेकिन जिन देशों में एंटीबायोटिक का अंधाधुंध इस्तेमाल होता है, उनमें भारत भी प्रमुख रूप से शामिल है। डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति है। विश्व को इससे निपटने के लिए एकजुट होकर रणनीति बनानी होगी।